

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> किसानों की खुशहाली और समृद्धि...



न्यायपालिका दबाव में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली। लोकतंत्र में विरोध करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कितनी जायज है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की राजनीतिक शैली पर एक तरह से गंभीर टिप्पणी कर दी है। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर विपक्षी नेताओं के मार्च निकाले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने दोटूक कहा, ‘न्यायपालिका को कोई दबाव में नहीं डाल सकता।’ देखा जाये तो यह टिप्पणी सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि उन राजनीतिक तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाती है, जिनमें अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। यहां सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी और विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक विरोध की सीमा और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के बीच का अंतर भूलते जा रहे हैं?

हम आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं तथा समर्थकों के सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने के मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने न्यायिक परिसरों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तुणमूल कांग्रेस सांसद महिआ मोझा और अन्य



संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने करीब 200 वकीलों के उस ज्ञापन का उल्लेख किया, जिसमें न्यायपालिका को कथित तौर पर दबाव में लेने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘ये हल्की-फुल्की बातें हैं और न्यायपालिका को कोई दबाव में नहीं डाल सकता।’ जब भाटिया ने अदालत के बाहर नेताओं के बयानों और न्यायिक परिसर की मर्यादा का सवाल उठाया, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हम हाथीदांत के मीनारों में नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि वे बाहर क्या बयान देते हैं और अदालत में क्या कहते हैं। हमें सब कुछ पता है।’ प्रधान न्यायाधीश के इन शब्दों को महज एक अदालती टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

10 अक्टूबर को कानून-व्यवस्था टूटने से बचाई : अनुराग

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान, पुलिस द्वारा समय रहते, उचित और कानूनी कदम उठाए जाने से कानून-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या टल गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार, जिन्होंने अदालत की अवमानना ??के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है, ने कहा कि 10 अक्टूबर को – जब कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था – तब उठाए गए एहतियाती कदम खुफिया इनपुट और जमीनी हालात के आकलन पर आधारित थे, जो लगातार बदल रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने पुलिस प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया, जिसमें दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाओं को विनियमित करना भी शामिल है। उन्होंने कहा ये कदम राष्ट्रीय राजधानी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए गए थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों और उठाए गए कदमों को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, और हर राष्ट्रीय राजधानी की अपनी कुछ संवेदनशील बातें होती हैं।



एशियाई खेल मेडलवीरों से मिले पीएम मोदी बोले, जुनून जीत में बदले तो चमकता है न्यू इंडिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, जिनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। हालांकि, तीन साल पहले हांगझोऊ में जीते गए ऐतिहासिक 106 पदकों की तुलना में यह संख्या कुछ कम रही, फिर भी 2026 का प्रदर्शन ऐतिहासिक था, क्योंकि यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का दूसरा सबसे सफल प्रदर्शन रहा। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान खिलाड़ियों ने उन्हें अपनी हस्ताक्षरित (साइन की हुई) जर्सी और हॉकी स्टिक भेंट की।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

यूपी-पंजाब समेत 17 राज्यों में अपडेट होगी वोटर लिस्ट

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 17 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे वे राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया की जानकारी दी है। आयोग के मुताबिक, पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल करना है। इसमें खास तौर पर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज गलतियों को सुधारने और सूची को सटीक व अद्यतन बनाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त हो रहा है। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तरीकों पर पूरा होगा।

माफिया अतीक अहमद गढ़ कसारी मसारी अब होगा ‘कृष्ण पुरी’

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद का गढ़ रहे प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा सियासी संदेश दे गए। उन्होंने कसारी मसारी का नाम बदलकर ‘कृष्णपुरी’ करने की घोषणा की। कहा कि माफियागिरी का दुस्साहस किया तो मिट्टी में मिलने को तैयार रहें। अवैध कब्जा करने वालों को बाप-दादा की संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ेगा। उस पर गरीबों के आवास बनेंगे। सीएम योगी ने कसारी मसारी में माफिया अतीक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर पद्म आवास योजना के लिए बृहस्पतिवार को भूमि पूजन किया। वहां 2-बीएचके वाले 602 फ्लैट बनाए जाते हैं। सीएम ने कहा कि माफिया अतीक व अशरफ जहां पैर रखते थे, जमीन उकती होती थी। सपा की सरकार उनके सामने घुटने टेकती थी और माफिया असलहा लहराकर दहशत फैलाते थे। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश को माफिया से मुक्त कराने का अभियान चलाया गया। असर अब दिखने लगा है।

विजिलेंस एफआईआर के खिलाफ पिनाराई विजयन को राहत नहीं

नई दिल्ली। केरल उच्च न्यायालय ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और उनके पति पी.ए. मोहम्मद रियास की उन अर्जियों को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने सीएमआरएल रिश्तत मामले में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने की अनुमति मांगी थी। भाजपा और कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुञ्जलनादन ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं, सीपीआई (एम) ने दावा किया है कि यह मामला झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। पार्टी का कहना है कि यह भाजपा और यूडीएफ की एक सोची-समझी चाल है, जिसका मकसद उनके नेताओं और वामपंथी दल को निशाना बनाना है। राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सरकार के लिए कोई झटका नहीं है, क्योंकि सरकार ने कानून के अनुसार काम किया है और इसमें कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं था। विजयन, वीणा और रियास को सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं मिली।

ज्ञानेश कुमार के समर्थन में उतरे 30000 लोग

नई दिल्ली। सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समर्थन में 3000 से ज्यादा जैन-जी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इसे देखकर कॉकरोचों के होश उड़ गए हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एक एक कॉकरोच के मुकाबले 10,000 देशभक्त सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी से परेशान लोगों ने अभिजीत दीपक के परखच्चे उड़ा दिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिजीत दीपक को देखते ही लोगों ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि देश को क्यों खराब कर रहा है? आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों के अलावा व्यापारी भी इन कॉकरोचों और विपक्षी दलों से बेहद परेशान हैं। दिवाली आने वाली है। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। लेकिन विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों की वजह से व्यापारियों का काम पूरी तरह से टप रहा। नवरात्रि के पहले तीन शुभ दिन निकल गए। लेकिन इस शुभ मौके पर कॉकरोचों की वजह से दिल्ली के व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ी। दिल्ली को हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मगर राहुल गांधी अड़ गए हैं कि ज्ञानेश कुमार, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सबका इस्तीफा लेकर रहूंगा।

सुप्रीम कोर्ट की रोक पर महिला पत्रकार को मिली राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि विरोध-प्रदर्शनों और भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों और पत्रकारों के बीच व्यवहार को लेकर राष्ट्रीय दिशानिर्देश तय किए जाएं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को कवर करने के दौरान, पुलिस ने कई पत्रकारों (जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं) के साथ मापीट की और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा, हम कुछ दिशानिर्देश तय करना चाहेंगे। यह टिप्पणी तब आई जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद, एक महिला पत्रकार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। अधिकारी का आरोप है कि जंतर-मंतर के पास एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, महिला पत्रकार ने उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी की और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया।

पूर्व आईएएस दित्या मित्तल ने बनाई जन नीति भारत पार्टी, 2027 में लड़ेंगी चुनाव

नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व अधिकारी दित्या मित्तल ने बृहस्पतिवार को ‘जन नीति भारत’ नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की और कहा कि उनकी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मित्तल ने बृहस्पतिवार को ‘एक्स’ पर एक वीडियो संदेश में कहा कि उनकी पार्टी नीति निर्माण की प्रक्रिया में आम लोगों को केंद्र में रखेगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान लगातार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे, न कि केवल चुनाव के समय। पार्टी के नाम और आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने के

फैसले की घोषणा करते हुए मित्तल ने कहा, ‘‘राजनीति आप पर शासन करती है। जन नीति में, आप ही वे होंगे, जो शासन करेंगे।’’ मित्तल ने कहा कि राजनीति में प्रवेश करने संबंधी उनकी पिछली अपील पर प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहजनक रही, क्योंकि उन्होंने जो फोन नंबर साझा किया था, उस पर बहुत-से लोगों ने संदेश भेजे थे। नयी पार्टी के पीछे के तर्क को समझते हुए मित्तल ने कहा, ‘‘समस्या दलों की कमी नहीं है, समस्या यह है कि लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती। कुछ लोगों की सुनी जाती है, लेकिन सभी की नहीं।’’ उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था के विपरीत, जिसमें विधायक अक्सर सरकार और

जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, ‘जन नीति भारत’ के प्रतिनिधियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह रहना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक दल भले ही एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते दिखें, लेकिन वे निर्णय-निर्माण को आम लोगों के हाथों से दूर रखने पर सहमत हैं।’’ मित्तल ने कहा कि जन नीति भारत के पास बड़े पैमाने पर विज्ञापन देने के लिए ‘सोच-समझ’ के बजाय वे घर-घर जाकर प्रचार करेंगे, जहां हर घर एक कार्यालय की तरह होगा और हर समर्थक एक प्रचारक की भूमिका निभाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें अपने गांवों और कस्बों में बुलाएं, उनके



संदेश को कम से कम तीन अन्य लोगों तक पहुंचाएं और राजनीति नहीं, जन नीति के नारे का प्रचार करें। मित्तल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बेंगलुरु की छात्रा रह चुकी हैं। उन्होंने 13 साल के करियर के बाद 30 अगस्त को भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।

इसके बाद उन्होंने 29 सितंबर को राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा की थी। नयी पार्टी के गठन के साथ ही मित्तल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को केंद्र में रखकर नीतियां बनाने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मुद्दों पर ध्यान देगी। मित्तल ने ‘जन नीति भारत’ पार्टी की नीतियों के निर्माण में जन भागीदारी, जरूरत आधारित फैसलों और सरकारी कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तीन संकल्प पेश किए हैं। अपने आठ मिनट 27 संकेद के वीडियो में उन्होंने कहा कि नीतियां प्रभावित लोगों

की जरूरतों के अनुरूप बननी चाहिए और उनके क्रियान्वयन में विशेषज्ञों की मदद ली जानी चाहिए। मित्तल ने देवकली देवी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी मांग पर स्कूल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन जमीन वन भूमि होने के कारण काम रोक दिया गया। उन्होंने औद्योगिक परियोजनाओं और मंजूरी देने की प्रक्रिया में अंतर पर सवाल उठाया। दूसरे संकल्प के तहत मित्तल ने सार्वजनिक कार्यों की प्राथमिकताएं लोगों की जरूरतों के आधार पर तय करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि फैसले चुनिंदा लोगों के प्रभाव के बजाय सामूहिक जरूरतों पर आधारित होने

चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने मोबाइल ऐप का सुझाव दिया, जिसके जरिये असुरक्षित स्थानों की जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर 100 शिकायतें मिलने पर भी रोशनी, पुलिस गश्त और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। मित्तल ने तीसरे संकल्प में सरकारी परियोजनाओं की लागत, समयसीमा और जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी सार्वजनिक करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आवास सहायता जैसी क्षेत्रीय लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर भेजी जानी चाहिए ताकि बिचौलियों की भूमिका कम हो।

गंगरेल बांध प्रभावितों का जल सत्याग्रह समाप्त

तीसरे दिन प्रशासन से सहमति बनी है. मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रभावितों का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगें रखेगा.

धमतरी। गंगरेल बांध के डूब प्रभावित परिवारों का अपनी मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह बुधवार शाम समाप्त हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त करने पर सहमति बनी। बैठक में तय किया गया कि जिला प्रशासन अगले 15 से 20 दिनों के भीतर राजस्व मंत्री और वन मंत्री के समक्ष डूब प्रभावितों के व्यवस्थापन के मुद्दे पर चर्चा करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपनी-अपनी बात रखेंगे।

गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर 12 अक्टूबर से शुरू हुआ जल सत्याग्रह तीसरे दिन समाप्त हुआ। बुधवार शाम निरीक्षण गृह गंगरेल में राजस्व, पुलिस और सिंचाई विभाग की मौजूदगी में चर्चा हुई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एसडीओपी और तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी शामिल रहे। बातचीत के दौरान प्रभावित परिवारों की मांगों और उनके लंबे समय से लंबित व्यवस्थापन के मुद्दे पर आगे चर्चा करने की सहमति बनी। गंगरेल बांध के निर्माण के दौरान 52 गांवों के लोगों की खेती की जमीन और मकान डूब क्षेत्र में आ गए थे। बांध निर्माण के बाद विस्थापन का दर्द झेल रहे प्रभावित परिवार लंबे समय से भूमि आवंटन और उचित व्यवस्थापन की मांग कर रहे हैं।



प्रभावितों का कहना है कि उनके हक और पुनर्वास से जुड़ा मामला वर्षों से लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश के करीब छह साल बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिवारों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। अपनी मांगों को लेकर डूब प्रभावितों ने 12 अक्टूबर को गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर जल सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों ने पानी में उतरकर अपने अधिकारों की मांग उठाई और व्यवस्थापन की समस्या का समाधान करने की मांग

की। तीन दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद बुधवार को प्रशासन के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद जल सत्याग्रह समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

अब मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी बात

बैठक में बनी सहमति के अनुसार, जिला प्रशासन 15 से 20 दिनों के भीतर राजस्व मंत्री और वन मंत्री के साथ डूब प्रभावितों के हित में नियमानुसार कार्रवाई को लेकर चर्चा करेगा। इसके बाद

मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

जल सत्याग्रह समाप्त होने से आंदोलन स्थल पर स्थिति सामान्य होने की राह खुली है, लेकिन डूब प्रभावितों की असल मांग व्यवस्थापन और भूमि आवंटन को लेकर है। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों और शासन के फैसले से ही स्पष्ट होगा कि वर्षों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को कब तक राहत मिल पाती है।

पीएचसी में लटका था ताला, गेट के सामने हुआ प्रसव, डॉक्टर और एएनएम निलम्बित

सूरजपुर। सूरजपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती महिला को रात में उप स्वास्थ्य केंद्र गणेशपुर लेकर आए, पर वहां कोई डॉक्टर और स्टाफ नहीं होने का आरोप परिजनों ने लगाया। स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा होने के कारण महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाया।

हालात ऐसे बने कि अस्पताल के गेट के सामने ही महिला का प्रसव हो गया, लेकिन जन्म के कुछ देर बाद नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी चिकित्सक राजेश पटेल और एएनएम प्रमिला गिरी को निलंबित कर दिया है। वहीं जांच और कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया है। दरअसल, पूरा मामला सूरजपुर जिले के गणेशपुर



प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां ग्राम पंचायत पवनपुरी के तलवापारा निवासी अनिर कुमार सारथी 14 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव के लिए लेकर पहुंचे थे। परिजनों के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ गई, लेकिन उस वक्त अस्पताल के गेट पर ताला लगा हुआ था। ऐसे में महिला को समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और अस्पताल के गेट के सामने ही प्रसव हो गया। इसके बाद नवजात की मौत हो गई।

घटना के बाद महिला की हालत को देखते हुए परिजन उसे रामानुजगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। इधर, नवजात की मौत से नाराज परिजन और

ग्रामीण 15 अक्टूबर को गणेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के गेट पर ताला लगाकर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का सवाल है कि जब सरकारी अस्पताल में रात के समय प्रसव जैसी आपात स्थिति में भी इलाज नहीं मिलेगा, तो फिर ग्रामीण मरीज कहां जाएंगे।

मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुनील अग्रवाल ने भी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा सरकार स्वास्थ्य को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थिति बहुत बुरी है। समय रहते प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो कांग्रेस प्रदर्शन करने को मजबूर होगी।

बलौदाबाजार पुलिस का नवरात्रि में सुरक्षा सख्त

बलौदाबाजार भाटापारा। जिले में अपराध नियंत्रण, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। 14 अक्टूबर को जारी पुलिस की अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसार, गिधपुरी में किराना दुकान की आड़ में गांजा बेचने के आरोप में दुकानदार और कथित सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। लवन में जुआ खेलते पांच लोगों को पकड़ा गया, जबकि सुहेला के प्रसिद्ध नवदुर्गा महोत्सव में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पैदल पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच अपराध अनुसंधान, साइबर जागरूकता और आपातकालीन सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 10 पुलिसकर्मियों को ‘COP OF THE MONTH’ सम्मान से नवाजा गया। गिधपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम गाड़कुसमी में पुलिस ने गांजा बेचने के आरोप में संतराम विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी किराना एवं खाई-खजाना दुकान की आड़ में गांजा बेच रहा था। मामले की जांच के दौरान कथित सप्लायर खेमन साहू का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया।185 पुष्टिया तैयार गांजा और थैले में रखी सूखा गांजा बरामद हुआ। जब गांजे का कुल वजन 978 ग्राम बताया गया है। पुलिस ने गांजे की अनुमानित कीमत करीब 11,750 रुपये बताई है। संतराम से पूछताछ के दौरान ग्राम भवानीपुर निवासी खेमन साहू का नाम



सामने आया। पुलिस का दावा है कि संतराम ने गांजा खेमन से खरीदकर लाने की बात बताई। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए खेमन साहू को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना गिधपुरी में अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जानकारी दी है। अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में लवन पुलिस ने ग्राम गिंदोला स्थित जोगी डबरी के पास कथित तौर पर जुआ खेल रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 3,130 रुपये नकद और 52 ताश पत्तियां जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ताश पत्तियों के जरिए रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों ने पूछताछ के दौरान रुपये का दांव लगाकर जुआ खेलने की बात स्वीकार की।

इस बार भी कटे-फटे बारदानों से बढ़ेगी किसानों की परेशानी

राजनांदगांव। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों के बीच बारदानों की व्यवस्था को लेकर कयाद तेज हो गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध 96 सहकारी समितियों में धान खरीदी के लिए मार्कफेड द्वारा बारदानों की व्यवस्था की जा रही है। खरीदी के दौरान पर्याप्त बारदाने उपलब्ध रहें, इसके लिए पुराने बारदानों के उपयोग के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और राइस मिलरों से बारदाने जुटाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नए बारदानों की व्यवस्था भी की जा रही है। उस पर भी विभाग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो दशहरा पर्व के बाद समितियों में बारदानों की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी तैयारी की जा रही है। धान खरीदी के दौरान बारदानों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खरीदी केंद्रों में किसानों से बड़ी मात्रा में धान की आवक होती है, जिसके लिए लगातार बारदानों की जरूरत पड़ती है ऐसे में विभाग के सामने सभी 96 समितियों में जरूरत के अनुसार बारदाने उपलब्ध कराने की चुनौती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्कफेड द्वारा अलग-अलग स्रोतों से बारदानों की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों की



माने तो इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। बारदानों की जरूरत पूरी करने के लिए पीडीएस दुकानों से खाली होने वाले बारदानों और राइस मिलरों से मिलने वाले बारदानों का उपयोग करने की तैयारी है। इसके साथ ही नए बारदानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। पुराने बारदानों में से उपयोग योग्य बारदानों को खरीदी कार्य में लगाया जा सकता है। हालांकि, कटे-फटे बारदानों की स्थिति और उनके उपयोग की पात्रता के अनुसार ही उनका इस्तेमाल किया जाना जरूरी होगा। पूर्व वर्षों की तरह इस बार भी कटे-फटे बारदाने परेशानी पैदा कर सकते हैं।जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध 96 समितियों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। खरीदी शुरू होने के बाद किसी केंद्र में बारदानों की कमी के कारण काम प्रभावित न हो, इसके लिए पहले से इंतजाम किए जा रहे हैं।

इलाज के लिए अस्पताल लाया तस्करी का आरोपी, चकमा देकर हुआ फरार

महासमुंद। नशीली टैबलेट तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल से फरार हो गया। उसे पेट के दाहिने हिस्से में तेज दर्द और झटके आने की शिकायत के बाद इलाज के लिए लाया गया था। आरोपी की निगरानी में दो पुलिस जवान तैनात थे, लेकिन गुरुवार सुबह वह अस्पताल से निकलने में कामयाब हो गया। घटना के बाद पुलिस उसकी तलाश के साथ अभिरक्षा में हुई चूक की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, सरायपाली पुलिस ने बुधवार को ओडिशा से नशीली टैबलेट की तस्करी के आरोप में 20 वर्षीय दिनेश सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया था। बाद में तबीयत बिगड़ने की शिकायत पर सरायपाली में प्राथमिक उपचार के बाद उसे महासमुंद के जिला अस्पताल रेफर किया गया।

अस्पताल में आरोपी की निगरानी के लिए पुलिस जवान खेमनलाल साहू और रामचरण यादव तैनात थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच एक जवान बाथरूम गया था,



जबकि दूसरा डॉक्टर के काम में व्यस्त था। इसी दौरान दिनेश वहां से फरार हो गया। बताया गया है कि आरोपी के पैर में रॉड लगी हुई थी। इसके बावजूद वह निगरानी से बचकर कैसे निकला, इसकी जांच की जा रही है। आरोपी को हथकड़ी लगाई गई थी या नहीं और फरारी के वक्त सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, यह भी जांच के अहम बिंदु हैं। पुलिस अस्पताल में लगे श्रृङ्खलू कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी के निकलने के रास्ते और फरारी से जुड़े घटनाक्रम का पता चल सके। आसपास के संभावित ठिकानों पर भी उसकी तलाश की जा रही है। मामले में सिटी कोतवाली में रूड़क दर्ज करने की कार्रवाई जारी है।

सिविल अस्पताल में आग से बचाव के सिखाए गए तरीके

एमसीबी। मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में आज आगजनी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए माॅक ड्रिल का आयोजन किया। नगर सेना के जवानों ने करीब दो घंटे तक अस्पताल परिसर में अभ्यास किया।अभ्यास के दौरान अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा गार्डों को बचाव के गुर सिखाए गए। आपको बता दें कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर आग लगने से स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है। खासकर उन मरीजों के लिए जो चलने-फिरने में असमर्थ होते हैं। इसी को देखते हुए यह माॅक ड्रिल की गई। जवानों ने बताया कि आग लगने पर सबसे पहले घबराना नहीं है। तुरंत अलार्म बजाकर सभी को सतर्क करना है और बचाव कार्य शुरू करना है ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। भगदड़ रोकने और मरीजों को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकालने के तरीके बताए गए।माॅक ड्रिल में चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों को प्राथमिकता पर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर से सुरक्षित निकालने का अभ्यास कराया गया। वाडों से निकासी, एग्जिट रूट को खाली रखने और आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया गया।

सुकमा पुलिस और सेवा पथ फाउंडेशन की अनूठी पहल

सुकमा। पुलिस की वर्दी पहनकर जवान भले ही मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हों, लेकिन उनके पीछे परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं का योगदान भी कम नहीं है। अब इन्हीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से सुकमा पुलिस ने एक नई पहल की है। पुलिस लाइन सुकमा में ‘सेवा पथ एक पहल’ के तहत निःशुल्क सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र के माध्यम से पुलिस परिवार की 150 महिलाओं को तीन महीने तक सिलाई प्रशिक्षण दी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मयंक गुजर ने कहा कि हर वर्दी के पीछे एक परिवार होता है। परिवार की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा महिलाएं संभालती हैं। पुलिस परिवार की इन्हीं महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। कार्यक्रम में संजीव कृष्ण ठाकुर ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि तीन महीने का यह प्रशिक्षण उनके लिए भविष्य की नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है।

शिक्षकों से वसूली मामले में यूट्यूबर व 3 आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर। पुलिस ने स्कूल में शिक्षकों से अवैध वसूली और वीडियो वायरल करने के मामले में कार्रवाई की है। यूट्यूबर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामला पस्ता थाना इलाके के प्राथमिक शाला पुटसु का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शाला पुटसु में पदस्थ सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान पाठक रुकमण बारीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया गया कि यूट्यूबर दीपक यादव एवं उसके सहयोगियों ने अपने फाउंडेशन के लिए 10 हजार रुपए की मांग की थी। इसके बाद 25 अगस्त को आरोपी श्रवण यादव एवं सूर्या यादव विद्यालय पहुंचे और बिना अनुमति वीडियो बनाने लगे। इस दौरान प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। आरोपियों ने रुपए नहीं देने पर वीडियो को यूट्यूब एवं फेसबुक पर वायरल कर बदनाम करने और प्रार्थी से निलंबित करवाने की धमकी भी दी। नौकरी के अनुसार यूट्यूबर दीपक यादव द्वारा अन्य आरोपियों के सहयोग से वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया।

च्वाइस सेंटर्स के क्यूआर कोड से धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। अलग-अलग जिलों के च्वाइस सेंटर संचालकों के क्यूआर कोड का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का रेंज साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में रायपुर निवासी दो आरोपियों अंकित आहूजा और आशीष केवटवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर बिलासपुर सहित रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, सकी और दुर्ग जिले के च्वाइस सेंटर संचालकों को निशाना बनाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, अब तक करीब 45 पीड़ितों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनके आधार पर धोखाधड़ी की अनुमानित रकम 20 से 25 लाख रुपये बताई गई है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 2 हजार रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल की गई एक बोलोनो कार, एक स्कूटी और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मामले में सबसे पहले बिल्हा मोड़ स्थित लक्ष्मी च्वाइस सेंटर के संचालक देवेंद्र रजक की शिकायत से हुई। शिकायत के अनुसार, 5 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे एक व्यक्ति बोलोनो कार से सेंटर पहुंचा।

अतिरिक्त कक्ष का डिटी सीएम विजय शर्मा ने किया भूमिपूजन

कवर्धा। कबीरधाम जिले में उच्च शिक्षा की अधोसंरचना मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने सहसपुर लोहारा स्थित शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय में 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने 15 लाख रुपये की लागत से बार्ड्रूवॉल और 5 लाख रुपये की लागत से बालिका शौचालय निर्माण कराने की घोषणा भी की। वहीं, युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और आधुनिक तकनीक के सही उपयोग का संदेश दिया। कॉलेज में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों से सीधे बात की और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज जीवन करियर निर्माण का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

बस्तर में छलका बाढ़ पीड़ितों का दर्द, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन

जगदलपुर। बाढ़ ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस बार जमकर तबाही मचाई। बस्तर में सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ से हुआ। किसानों की खड़ी फसल खेतों में डूब गई। घर से लेकर दुकान तक पानी में समा गए। लगातार बांधों से छोड़ा गया पानी नदियों के जलस्तर को बढ़ाता रहा, जिससे बाढ़ कई दिनों तक बना रहा। बाढ़ ने जहां किसानों की आर्थिक रुप से कमर तोड़ दी, वहीं मकान में रखा गया अनाज भी भींगकर खराब हो गया। किसान दाने-दाने को मोहताज हो गया। बाढ़ पीड़ित किसान अब सरकार मदद और मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। बस्तर जिला मुख्यालय में आज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किसान कांग्रेस के बैनर तले किया। किसानों ने बस्तर कलेक्ट्रेट का घेराव कर वहां नारेबाजी की। किसानों की मांग थी कि सरकार मुआवजे का सर्वे कर उनको



आर्थिक मदद जल्द से जल्द दे। बस्तर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने आए किसानों के साथ उनके परिवारवाले भी मौजूद थे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दस दिनों के भीतर उनको आर्थिक मदद नहीं दी जाती है, तो जगदलपुर में ट्रैक्टर से चक्काजाम करने को बाध्य होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ

खानापूर्ति कर रही है। बाढ़ प्रभावित किसानों को 65 हजार देना पड़ेगा। खेती के लिए किसानों द्वारा लिए गए केसीसी लोन को माफ करना होगा। मकान नुकसान में कच्चे दस दिनों के भीतर उनको महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि तीन महीने का यह प्रशिक्षण उनके लिए भविष्य की नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है।

करीब 30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि प्रदान किया गया है। फसल क्षति का आकलन चल रहा है। जिसमें 50 लाख मुआवजा प्रभावितों के खाते में चला गया है। किसानों के ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाया जाएगा सीपी बघेल, अपर कलेक्टर बस्तर किसान कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वो शहर को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसान कांग्रेस का कहना है कि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन किसानों को जब मदद देने की बारी आई तो सरकार मौन है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दयाराम कश्यप ने कहा, आगामी 10 दिनों के बाद ट्रैक्टर से पूरे जगदलपुर शहर को ब्लॉक किया जाएगा। और राज्य शासन को चेतावनी दिया जाएगा और उचित मुआवजे की मांग की जाए।

बजरंग दल और आयोजकों के बीच झूमाझटकी

दुर्ग। नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग जिले में जगह-जगह गरबा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित हॉकी ग्राउंड में गरबे के आयोजन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। इस दौरान जमकर झूमाझटकी और मारपीट भी हुई।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व महापौर और दुर्ग शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धीरज बाकलीवाल की ओर से आयोजित दो दिवसीय गरबा नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान बजरंग दल के लोगों ने गरबा में फिल्मी गाने और मुस्लिम लड़कों की उपस्थिति का विरोध किया। वायरल वीडियो में बजरंग



दल के जिला संयोजक मंच पर चढ़कर माइक से विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आयोजक और बजरंग दल के जिला संयोजक राम लोचन तिवारी के बीच मारपीट भी हुई। वीडियो में रामलोचन कहते नजर आ रहे हैं कि यह पर्व मां दुर्ग की उपासना का है। यहां फिल्मी गाने न बजाया जाए और किसी

मुस्लिम को यहां इंटी न दी जाए और आर दी जा रही है तो उनके मां-बहन बेटियों को भी यहां लाया जाए। इस विरोध के दौरान गरबा आयोजकों ने बजरंग दल के विरोध पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से गुरुवार को लोक भवन में छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष तोमन साहू ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य के 13 जिलों में जिला रेड क्रॉस समितियों की समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने की जानकारी दी और इसका प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा। साहू ने राज्यपाल को जिलों में रेड क्रॉस की गतिविधियों और संचालित कार्यक्रमों के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया। डेका ने शेष जिलों में भी जिला रेड क्रॉस समितियों की समीक्षा बैठक आयोजित करने के निशे दिए। उन्होंने रेड क्रॉस की गतिविधियों का विस्तार करने पर जोर दिया, ताकि जरूरतमंद लोगों तक सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य युगल सिन्हा उपस्थित थे।

राजेंद्र कंवर मंदिर हसौद के नये थाना प्रभारी, आशीष यादव अभनपुर गये

रायपुर। बोते कल रायपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश से मंदिर हसौद थाना भी प्रभावित हुआ है। सिलयारी में पदस्थ रहे थाना प्रभारी राजेंद्र कंवर को मंदिर हसौद थाना का प्रभारी बनाया गया है वहीं मंदिर हसौद में पदस्थ थाना प्रभारी आशीष यादव को अभनपुर में थाना प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। कथित राजनैतिक संरक्षण प्राप्त क्षेत्र के असामाजिक तत्वों सहित गांव-गांव में बिक रहे अवैध शराब, गांवा व नशीली गोलियों सहित हो रहे जुआ पर रोक लगा आम ग्रामीणों पर पुलिसिया विश्वास कमान करना उनके लिये प्रमुख चुनौती होगी। बोते दिनों कथित जन्मोत्सव के नाम पर ग्राम टेकारी के रमशानघाट में एकत्रित हुये ग्राम के ही पुलिसिया रिकाडंभारी युवकों के साथ एक युवती व 8-10 बाहरी युवकों को ग्रामीणों द्वारा ललकारने के बाद भाग खड़े होने की शिकायत ग्राम के निवासी किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा व पंचायत द्वारा किये जाने के बाद लगातार पुलिसिया दबिश के बाद भी पुलिस पकड़ से बच रहे स्थानीय असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी कर ग्रामीणों को भयमक करना भी एक चुनौती रहेगा।

त्रिलोकी माँ कालीबाड़ी में दुर्गोत्सव की शुरुआत आज से

रायपुर। श्री श्री शारदीय दुर्गात्सव समिति, त्रिलोकी माँ कालीबाड़ी डॉ. राजेंद्र नगर में कल 16 अक्टूबर को महाशष्ठी पूजा से दुर्गाोत्सव की भव्य शुरुआत होगी। 21 अक्टूबर को सिंदुर खेला और विसर्जन के साथ दुर्गा पूजा का समापन होगा। समिति का यह 46वाँ वर्ष है। समिति के सचिव विवेक बर्धन ने बताया कि इस समिति का दुर्गाोत्सव रायपुर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित बंगाली पद्धति के पूजा आयोजनों में से एक है। 16 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से महाशष्ठी पूजा होगी और फिर पुष्पांजलि का आयोजन होगा। सायं 6 बजे से बोधन, आमंत्रण व अधिवास और सायं 7:30 बजे संध्या आरती का आयोजन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को नव पत्रिका स्नान, महा सप्तमी पूजा 18 अक्टूबर को अतिरिक्त सप्तमी पूजा, 19 अक्टूबर महा अष्टमी पूजा, पुष्पांजलि, संधि पूजा, बलिदान संध्या आरती, 20 अक्टूबर महानवमी पूजा, होम (हवन) तथा 21 अक्टूबर को महादशमी पूजा, दर्पण विसर्जन और सिंदूर बरन का आयोजन किया जाएगा। समिति द्वारा सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी के पानव दिनों पर दोपहर एक बजे से भव्य भोग वितरण (भंडारा) का आयोजन किया जाएगा।

सड़क दुर्घटना में विधायक मोहल्ले के भाई समेत तीन की मौत

रायपुर। बिलासपुर संभाग के तखतपुर में गुरुवार की सुबह हुई सड़क दुर्घटना में पूर्व खाद्य मंत्री एवं मुंगेली से भाजपा विधायक के भाई समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना तखतपुर की बताई जा रही है। बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह रोज की तरह पुनू लाल मोहल्ले के भाई अधीन दास मोहल्ले सुबह मॉर्निंग वॉक में अपने दो साथियों के साथ मुख्य मार्ग मे निकले हुए थे। उसी दरमियान तेज गति से मुंगेली की ओर जा रही पिकअप वेन ने उन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक व्यक्ति ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि दो अन्य लोगों को गंभीर हालत में मुंगेली जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जराहागांव के थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों में अधीन मोहले, बहुबु बघेल और गंगा राम शामिल है। अधीन मोहले जो मुंगेली विधायक मोहले जी के बड़े पिता जी के बेटे थे।

मंत्री राजवाड़े की पहल से 6.97 करोड़ रुपये के सड़क-पुल कार्यों को मिली स्वीकृति

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री और भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी रावबाई के प्रयासों से भटगांव विधायकभा क्षेत्र में आवागमन सुविधाओं के विस्तार के लिए दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इन कार्यों पर कुल 6 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वीकृत कार्यों में गंगोटी-शिवप्रसादनगर से डुमरिया मार्ग पर गोबरी नदी में उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल है। इस कार्य के लिए 3 करोड़ 51 लाख 29 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुल बनने से नदी के दोनों ओर बसे गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा।

राजधानी/छत्तीसगढ़

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना (शहरी) की समीक्षा बैठक संपन्न

आवास जल्द पूरा करने वाले ह्तिगाहियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश

रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में आज मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और 1.0 के क्रियान्वयन एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि जो हितग्राही अपने आवास का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0: बैठक में लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत चल रही आवास निर्माण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।



इसके साथ ही, भागीदारी में किरायती आवास घटक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण स्थल में परिवर्तन के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इस योजना के तहत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को कटौती के बाद संशोधित परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय प्रशासन विभाग के विभिन्न अन्य प्रस्तावों की भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत कुल 2,43,087 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2 लाख 25, हजार 411 आवास पूरी तरह से पूर्ण

हो चुके हैं। 17 हजार 368 आवासों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। वहीं, बीएलसी घटक के अंतर्गत स्वीकृत 2 लाख 6 हजार 118 मकानों में से 1 लाख 96 हजार 144 मकान पूर्ण हो चुके हैं और 9 हजार 666 आवासों का निर्माण विभिन्न चरणों में जारी है।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (राज्य शहरी विकास अभिकरण) सुमित अग्रवाल सहित ऊर्जा, वित्त, आवास एवं पर्यावरण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगर तथा ग्राम निवेश, हाउसिंग बोर्ड, हुडको और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर जिले के 17 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण तीन फर्मों को कारण बताओ नोटिस

रायपुर। कैंसररोधी औषधियों के आयात, उपलब्धता और मूल्य संबंधी प्रावधानों की जांच के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला रायपुर द्वारा निरीक्षण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार तथा स्वास्थ्य सचिव और नियंत्रक के मार्गदर्शन में विभाग की टीम औषधियों से संबंधित दस्तावेजों और नियमों के अनुपालन की जांच कर रही है। इसी क्रम में 14 अक्टूबर को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल स्थित फार्मेसी तथा संजीवनी केयर हॉस्पिटल स्थित फार्मेसी में उपलब्ध कैंसररोधी औषधियों की जांच की गई। संबंधित फर्मों से औषधियों के ऋय-विक्रय से जुड़े दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं। औषधियों के आयात, ऋय-विक्रय तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जिले में कुल 17 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में तीन



फर्मों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किए गए हैं। संबंधित फर्मों से स्पष्टीकरण प्राप्त होने और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान का उद्देश्य औषधियों की गुणवत्ता एवं वैधता सुनिश्चित करने के साथ ही मूल्य संबंधी प्रावधानों के पालन की जांच करना तथा आम नागरिकों के हितों और जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं के संबंध में लागू नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा सतत निगरानी की जा रही है।

घने जंगलों के बीच दंतेवाड़ा-सुकमा सीमा पर बसे 228 घरों तक पहुंचा नल से जल

रायपुर। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा पर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एडपाल और डोडपाल गांवों के 228 परिवारों को अब घर पर ही नल से पेयजल मिल रहा है। जल जीवन मिशन से इन दूरस्थ गांवों में वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या दूर हुई है। पहले ग्रामीणों को पेयजल के लिए हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता था। अब घर-घर नल कनेक्शन मिलने से विशेष रूप से महिलाओं की दिनचर्या आसान हुई है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण जीवन में आए बदलाव की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर कटेकल्याण विकासखंड की ग्राम पंचायत एडपाल के 137 और उसके आश्रित ग्राम डोडपाल के 91 घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। दोनों गांवों को ‘हर घर जल ग्राम’ का दर्जा भी मिल चुका है।

घर तक पानी पहुंचने का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिला है। पहले गर्मी और बरसात के दिनों में भी उन्हें पानी के लिए घर से दूर जाना



पड़ता था। इसमें सुबह का काफी समय बीत जाता था। अब पानी लाने की मशक़त से राहत मिलने के साथ घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल और आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए अधिक समय मिल रहा है।

एडपाल की वार्ड पंच बुदरी मंडावी और ग्रामीण महिला जोगी मरकाम बताती हैं कि घर में नल लगने से पानी की चिंता दूर हुई है। महिलाएं अब सब्जी बाड़ी, वनोपज संग्रहण और खेती-किसानी के कामों में अधिक समय दे पा रही हैं। बच्चों को भी पानी लाने में समय लगाने के बजाय पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। इन गांवों में पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी महिलाओं ने संभाली है।

भूपेश बघेल और दीपक बैज के बयान पर सियासी घमासान

क्या बिक जाएगा भिलाई स्टील प्लांट?



उनके प्रिय खरीददार मुआयना करने आ रहे हैं। बघेल ने आगे लिखा है कि मोदी जी समझ लें कि बीएसपी छत्तीसगढ़ की आत्मा है और हम छत्तीसगढ़वासी इसे किसी सूरत में बिकने नहीं देंगे। किसी भी सूरत में नहीं। यह बात छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता भी समझ लें कि बीएसपी बिकाऊ नहीं है।

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी

कि भिलाई स्टील प्लांट और एनएमडीसी को नहीं बेचा जाएगा? बैज ने भिलाई स्टील प्लांट को लेकर भूपेश बघेल के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश के सार्वजनिक उपक्रमों और संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है। सीमेंट कंपनियों, पावर कंपनियों, नगरानर स्टील प्लांट और अन्य औद्योगिक इकाइयों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अब भिलाई स्टील प्लांट को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।

दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने की दिशा में आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में कोई भी

जिला न्यायालय ने तीन गांजा तस्करों को 15-15 वर्ष की सुनाई सजा

कांकर। गांजा तस्कारी के एक बड़े मामले में कांकर की जिला न्यायालय ने गुरुवार को तीन गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक कुबेर जैन ने पैरवी की।

इस मामले में 02 दिसंबर 2021 को तीनों आरोपियों को 55 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने तीनों गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 02



दिसंबर 2021 को चारामा के कोरर चौक में पुलिस ने गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान राजेश राजपूत, निवासी सीहोर के रूप में हुई। दूसरे आरोपी की पहचान नीलेश शर्मा और तीसरे आरोपी की पहचान पवन पाल निवासी रायसेन के रूप में हुई। तीनों के पास अलग-अलग बैग में कुल

55 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 20(बी) के तहत केस दर्ज किया। उसके बाद यह केस कोर्ट में पेश किया गया. 5 साल तक अदालत में केस चला. उसके बाद तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया है और सजा का ऐलान किया।

वीबी-जी रामजी से बना प्रदेश का पहला सोलर बालिका शौचालय

■ बेटियों को मिली आधुनिक सुविधाओं की सोगात

रायपुर। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) के अंतर्गत संचालित ‘मेरी बेटिटूमेरा अभिमान’ अभियान के तहत रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत तरां के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रदेश का पहला सोलर बालिका शौचालय बनाया गया है। लगभग 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक शौचालय में सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था के साथ दिव्यांग बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे विद्यालय की 70 छात्राओं और दो महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश की बेटियों के सम्मान के लिए वीबी-जीरामजी के अंतर्गत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटिटूमेरा अभिमान’ अभियान प्रारम्भ किया है। इस अभियान के तहत 26 जनवरी 2027 के गणतंत्र दिवस तक पूरे राज्य के सभी ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के



लिए शौचालय का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बेटियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

ग्राम तरां में शौचालय निर्माण के लिए वीबी-जी रामजी योजना से 5 लाख रुपए तथा कलेक्टर श्री गौरव सिंह द्वारा गौण खनिज विकास मद से 2 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। भवन की छत पर सोलर पैनल स्थापित किया गया है, जिससे प्रकाश की व्यवस्था होगी। पानी की उपलब्धता के लिए नल एवं सिंटेक्स टंकी लगाई गई है। इसके साथ बालिकाओं की सुविधा के लिए सेनेटेरी पैड इंसिनिरेटर भी लगाया गया है। दिव्यांग

बालिकाओं की सुविधा के लिए अलग शौचालय, रैंप और सहारे के लिए रेलिंग बनाई गई है। परिसर में पेवर ब्लॉक, पौधरोपण एवं साफ-सफाई की व्यवस्था भी की गई है।

ग्राम तरां के इस विद्यालय में पूर्व में निर्मित शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका था। इसके कारण छात्राओं को कई बार शौचालय के उपयोग के लिए घर जाना पड़ता था, जबकि महिला शिक्षिकाओं को पंचायत भवन की सुविधा का सहारा लेना पड़ता था। इस समस्या से छात्राओं की पढ़ाई और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहे थे। विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए एव शौचालय का निर्माण स्वीकृत किया गया, जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों और ग्रामीणों के सहयोग से पूर्ण किया गया।

नया शौचालय बनने से छात्राओं में खुशी है। उन्होंने बताया कि पहले शौचालय के अभाव में काफी परेशानी होती थी और कई बार विद्यालय आने का मन भी नहीं करता था। अब स्वच्छ एवं सुविधाजनक शौचालय उपलब्ध होने से वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी।

राशन के दामों में बढ़ोतरी पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कसा तंज

■ कहा- महतारी वंदन में दिया पैसा वसूल रही है सरकार

रायपुर। लगातार बढ़ती महंगाई पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सप्ताह के पहले दिन से चावल, दाल, राशन सामग्री पर सरकार ने दाम बढ़ाए। पेट्रोल-डीजल महंगे हुए। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। आम-जनता के लिए यात्री बस किराए बढ़ाया गया। एक साल में दो बार 75 प्रतिशत से अधिक किराया बढ़ाया गया। महतारी वंदन के नाम से पैसा देकर आम जनता से सरकार पैसा वसूलने का काम कर रही है।

धान खरीदी से पहले पटवारीयों की हड़ताल पर दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में नवंबर महीने से धान खरीदी होना है। पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार को तत्काल बात कर हड़ताल को खत्म करना चाहिए। यह पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी ऐसा हुआ



था। इस कारण कई किसान धान नहीं बेच पाए थे। सरकार जानबूझ कर ऐसा कर रही है,

ताकि धान खरीदना ना पड़े। कौशल्या माता धाम में भगवान राम की अब तक नई मूर्ति नहीं लगने पर दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम से मंदिर बना लो। मंदिर में चढ़ावा चोरी कर लो। गौ माता के नाम से चारा खा लो। सरकार में यही चल रहा है। 15 साल भी यही चल रहा था। भगवान राम के नाम से यह चंदा चोरी करने वाले है।

उन्होंने कहा कि भगवान राम और कौशल्या माता की चिंता क्या करेंगे। मूर्ति तैयार है, अभी तक मूर्ति क्यों नहीं लग रहे हैं। इनको जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार में मूर्ति बदलने का निर्णय

हुआ था, हमारी सरकार में मूर्ति तैयार की गई है। कोई मूर्ति गलत नहीं है। यह मूर्ति नहीं लगाना चाहते हैं। यह राम के नाम के राजनीति करते हैं। गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं। मंदिरों का चंदा चढ़ावा चोरी करना है, यही इनका धंधा है। आदिवासी विभाग का नाम बदलने को लेकर दीपक बैज ने कहा कि सरकार लगातार आदिवासी हितों को दरकिनार कर कुचलने का काम कर रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री और मंत्री मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। आदिवासी विभाग को बदल कर जनजाति विभाग ? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को आदिवासी समाज से। हम इसका पूरा विरोध करते है तत्काल निर्णय वापस ले। ये सरकार आदिवासी विरोधी है।

बिजली बिल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि साल भर में दो-दो बार बिजली बिल बढ़ाया गया है। इस लग रहे हैं। इनको जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार में मूर्ति बदलने का निर्णय

हल्दी बीज वितरण में अनियमितता की शिकायत पर जाँच शुरू

रायपुर। कृषि विभाग के अनुशांगिक संस्था उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 में राज्य पोषित मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हल्दी बीज वितरण में कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। कृषि मंत्री राम विचार नेताम के निर्देशानुसार मामले की जाँच प्रारंभ कर दी गई है तथा जाँच के लिए संचालनालय स्तर से टीम भी गठित की गई है।

जिलों में हल्दी बीज वितरण से संबंधित शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा जिला अधिकारियों से हितग्राहीवार रोपित बीज की मात्रा, बीज प्रदायक संस्थाओं द्वारा प्रदाय बीज की मात्रा एवं गुणवत्ता तथा हल्दी बीज रोपण करने वाले

कृषकों को भुगतान की गई अनुदान राशि की स्थिति सहित आवश्यक जानकारी और अभिलेख माँगे गए हैं।

उद्यानिकी विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कृषकों द्वारा रोपित किये गये हल्दी बीज से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज, भुगतान संबंधी विवरण तथा फसल के भौतिक सत्यापन की जानकारी निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाए, ताकि शिकायतों की तथ्यात्मक जाँच कर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

जाँच प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों के खेतों में रोपित हल्दी फसल की वास्तविक स्थिति, रोपित रकबा का सत्यापन करने के लिए डिजिटल क्रीप सर्वे कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राहुल गांधी के पक्ष में आया विपक्ष

सनत जैन

भारत की राजनीति बड़ी तेजी के साथ बदलती हुई दिख रही है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच में राहुल गांधी की स्वीकारता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद होने का लाभ भाजपा को मिलता रहा है। भाजपा की रणनीति रहती थी, विपक्ष में लगातार मतभेद बने रहें और चोटों का बंटवारा होता रहे, ताकि इसका फायदा भाजपा को मिले। अब स्थितियां बड़ी तेजी के साथ बदलती हुई दिख रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तथा चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया का केंद्रीकरण कर के कंप्यूटर के माध्यम से चुनाव परिणाम और मतदाता सूची को प्रभावित किया जा रहा है। उसको लेकर अब सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने अस्तित्व की चिंता में जुट गए हैं। यदि समय रहते क्षेत्रीय दलों ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस डर और भय के कारण ममता बनर्जी जैसी सशक्त महिला राजनीतिज्ञ इंडिया गठबंधन की ओर बिना शर्त आकर्षित हुई हैं। उन्हें भी समझ आ गया है, कम्युनिस्ट पार्टी से तो कभी भी लड़ा जा सकता है। कांग्रेस के समर्थन बिना पश्चिम बंगाल में अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, आज भी कांग्रेस पार्टी का गांव-गांव में अस्तित्व बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का संगठन जब सबसे ज्यादा कमजोर था, कोई मजबूत नेता कांग्रेस में नहीं था। उस समय भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 300 से अधिक सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर वोट पाने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस पार्टी चुनौती दे सकती है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है। पिछले 12 वर्षों मे भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले रखा था। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, पप्पू हैं, इसके पीछे एक ही रणनीति थी। जब भी भाजपा को चुनौती मिलेगी, तो वह कांग्रेस पार्टी से मिलेगी। जब तक राहुल गांधी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में वजूद रहेगा, तब तक भाजपा को कोई खतरा नहीं होगा। स्थिति इस तरह से बदलेगी, इसका अंदाजा भाजपा के नेताओं को नहीं था। देखते ही देखते राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की चुनौती मिलेगी, यह तो सपने में भी भाजपा ने नहीं सोचा था। इंडिया गठबंधन इस तरह से मजबूत होगा, इसकी कल्पना भी भाजपा नेताओं को नहीं थी। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर के इतने बड़े दुष्परिणाम सामने आएंगे, इसकी भाजपा ने कल्पना में नहीं की थी। न्यायपालिका का जो समर्थन सरकार के पक्ष में था अब वह भी कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की स्थितियां महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तेजी से बदल रही हैं, उसने सरकार और भाजपा की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे 2012 से 2014 के बीच में कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के नेता घिरे थे। राहुल गांधी ने जिस साहस के साथ प्रधानमंत्री का मुकाबला किया है। उसके कारण राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ आम जनता के बीच में भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, जिनकी पहचान अब उत्तर-दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं में एक राष्ट्रीय और सशक्त नेता के रूप में बनी है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

19- थेरावाद या प्रारम्भिक पाली बौद्धधर्म

गतकं से आगे...

(1) सुत्तपिटक में बुद्ध के उपदेश दिये गये हैं जिनमें बौद्ध सिद्धान्तों का मूलस्वरूप पाया जाता है। सुत्तपिटक पांच निकायों में विभक्त है जिनके नाम-1 दीवज्ज निकाय, 2 मज्झिम निकाय, 3 संयुत्त निकाय, 4 अंगुत्तर निकाय और 5 खुदक निकाय हैं। धम्मपद जो कि बौद्धों की गीता समझी जाती है. खुदक निकाय के अन्तर्गत ही है।

(2) विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिये संयम और नियम की व्यवस्थाएँ की गयीं हैं।

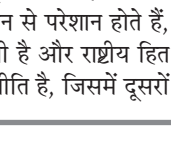
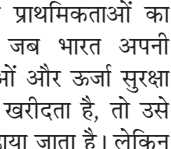
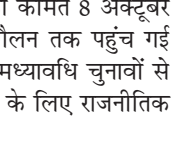
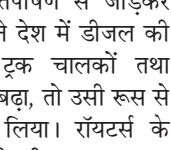
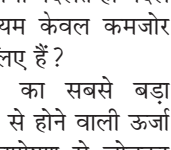
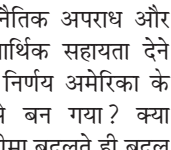
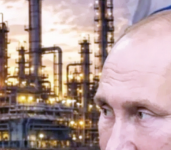
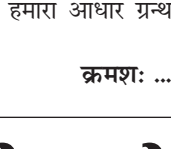
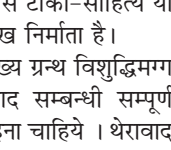
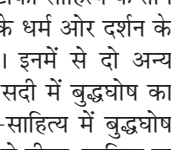
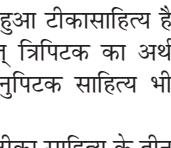
(3) अभिधम्मपिटक में बौद्ध सिद्धान्तों का जो कि मूलरूप में सुत्तपिटक में आ गये हैं दार्शनिक विवेचन है, इस प्रकार अभिधम्मपिटक बौद्ध दर्शन का आधारभूत है। पहिले दोनों पिटक, अर्थात् सुत्तपिटक और विनयपिटक प्राचीन माने जाते हैं परन्तु अभिधम्म की प्राचीनता में संदेह किया जाता है। टीका साहित्य त्रिपिटक के साथ ही पाली

त्रिपिटक की व्याख्या में लिखा हुआ टीकासाहित्य है जिसे अट्ठ-कथा-साहित्य अर्थात् त्रिपिटक का अर्थ कथन सम्बन्धी साहित्य या अनुपिटक साहित्य भी कह देते हैं।

बौद्ध दर्शन की दृष्टि से इस टीका साहित्य के तीन ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं जो थेरावाद के धर्म और दर्शन के आधारभूत समझे जा सकते हैं। इनमें से दो अन्य बुद्धघोष के हैं। ईसा की चौथी सदी में बुद्धघोष का जन्म हुआ। त्रिपिटक के टीका-साहित्य में बुद्धघोष का नाम सर्वोपरि है, एक प्रकार से टीका-साहित्य या अट्ठ-कथा-साहित्य का वह प्रमुख निर्माता है।

(1) बुद्धघोष का सत्रसे मुख्य ग्रन्थ विषुद्धिमग्ग है जिसे एक प्रकार से थेरावाद सम्बन्धी सम्पूर्ण विद्या-विज्ञान का विश्व कोष कहना चाहिये । थेरावाद सम्बन्धी पूर्ण परिचय के लिये हमारा आधार ग्रन्थ यही है।

क्रमशः ...



उत्तरप्रदेश कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई जूते-चप्पल तक आई

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कौन किस पाले में चला जाए, इसकी गारंटी न दिल्ली दे सकती है, न लखनऊ का कोई सियासी पंडित। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर भी यही सवाल उठने लगा है कि क्या वह एक बार फिर भाजपा का दामन थाम सकते हैं ? सवाल उठ रहा है कि जिस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में बार-बार चुनौती दी, क्या वही नेता अब कांग्रेस में अपनी सियासी जमीन खिसकती देख पुराने घर की ओर लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं ? फिलहाल यह अटकल है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छिनने, नए नेतृत्व से तनातनी और लखनऊ कांग्रेस दफ्तर में जूते-चप्पल चलने के बाद इन चर्चाओं को हवा जरूर मिल गई है।

वैसे कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन यूपी कांग्रेस का हाल देखिए, यहां लंका ढहाने के लिए विपक्ष को मशक़त करने की जरूरत ही क्या है, जब अपने ही लोग एक-दूसरे से दो-दो हाथ करने को तैयार बैठे हों! हम आपको बता दें कि अजय राय को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर आराधना मिश्रा %मौन% को जिम्मेदारी सौंप दी गई। नई व्यवस्था में इमरान मसूद को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। मगर संगठन में बदलाव का यह फैसला पुराने नेतृत्व और उसके समर्थकों के बीच सहज रूप से स्वीकार नहीं हुआ। अजय राय की नाराजगी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि उन्हें हटाने के तरीके से वह असहज थे। उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका और राजनीतिक हैसियत को नजरअंदाज किया गया।

देखा जाये तो यूपी की राजनीति में पद केवल नाम के आगे लगाने वाला तमगा नहीं होता। उसके साथ समर्थकों की फौज, टिकट की दावेदारी, संगठन पर

पकड़ और भविष्य की सियासी संभावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उतरना किसी नेता के लिए महज जिम्मेदारी बदलना नहीं, अपने प्रभाव का हिसाब-किताब भी होता है। यही वजह है कि अब चर्चा चल रही है कि कांग्रेस उन्हें गुजरात जैसे किसी दूसरे राज्य में संगठनात्मक जिम्मेदारी देकर मनाने की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ भाजपा में वापसी की संभावना भी सियासी गलियारों में तैर रही है। उल्लेखनीय है कि अजय राय 1996 से 2009 तक भाजपा में रहे और उसके टिकट पर तीन बार विधायक चुने गए थे।

दूसरी ओर, लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ, वह महज दो नेताओं के समर्थकों की कहासुनी मानकर टाल देने वाला मामला नहीं है। आराधना मिश्रा के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान अजय राय और ममता चौधरी से जुड़े गुट आमने-सामने आ गए। विवाद रास्ता देने और अध्यक्ष को लेकर हुई टिप्पणी से शुरू हुआ बताया गया, लेकिन देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की और जूते-चप्पल तक पहुंच गया था। देखा जाये तो इस घटना ने यूपी कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी को फिर उजागर कर दिया है। पार्टी में कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेताओं की फौज दिखाई देती है। हर नेता को अपना खेमा चाहिए, हर खेमे को अपनी हैसियत चाहिए और हर हैसियत को संगठन में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। सवाल यह है कि जब पार्टी कार्यालय में ही नेतृत्व की इज्जत और अनुशासन की हिफाजत नहीं हो पा रही, तो गांव-कस्बों में संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा ?

एक ओर चुनाव सामने हैं दूसरी ओर ऐसे वक्त पर अगर पदभार ग्रहण समारोह में जूते चल रहे हैं, तो टिकट बंटवारे, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और चुनावी गठबंधन के वक्त यह खींचतान किस मुकाम पर पहुंचेगी

निष्पक्षता की नसीहतः दोहरे मानदंड छोड़ें, संप्रभुता का सम्मान करें

नितिन गौतम

संयुक्त राष्ट्र के हालिया सत्रों की कुछ अनावश्यक बयानबाजी के मद्देनजर भारत ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र एवं उससे जुड़ी संस्थाओं को निष्पक्षता बरतने, बिना किसी दोहरे मापदंड के काम करने और देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने की जो सलाह दी है, वह समयानुकूल होने के साथ वैश्विक संस्थाओं के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़े मानवाधिकार संगठन का रुख चुनिंदा देशों के प्रति पूर्वाग्रह से प्रसित नजर आया है।

एक तरफ जहां गंभीर मानवाधिकारों के हनन, आतंकवाद को पनाह देने वाले मुल्कों और तानाशाही व्यवस्थाओं पर वैश्विक संस्थाएं अक्सर चुप्पी साध लेती हैं या बेहद नरम रुख अपनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे जीवंत और विशाल लोकतंत्र के आंतरिक मामलों पर अनावश्यक और असंतुलित टिप्पनियां करती हैं। चाहे नागरिकता कानून हो, आंतरिक सुरक्षा के उपाय हों या न्यायपालिका के फैसले, अंतरराष्ट्रीय मंचों से अक्सर ऐसी टिप्पनियां आती हैं, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर होती हैं। भारत ने इसी दोहरे मानदंड पर गहरी आपत्ति जताई है।

जब आतंकवाद की बात आती है, तो वैश्विक परिभाषाएं बदल जाती हैं और जब किसी संप्रभु राष्ट्र में कानून-व्यवस्था की बात आती है, तो ‘मानवाधिकारों’ का चरमा पहन लिया जाता है। यह रवैया वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता को गंभीर चोट पहुंचाता है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने चिंता जताई थी, जिसे तत्काल भारत ने ‘अनावश्यक’ और देश के आंतरिक मामलों



में ‘अस्वीकार्य हस्तक्षेप’ बताया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों फ्रांस में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन इस कार्यालय ने कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझी। इसको ही लक्ष्य करते हुए भारत ने कहा है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त और उनके कार्यालय को राजनीतिकरण, अपनी सुविधानुसार मुद्दों के चयन और दोहरे मानदंडों से बचना चाहिए। भारत का यह तर्क भी वाजिब है कि मानवाधिकार की व्याख्या सार्वभौमिक होनी चाहिए और इसे लागू करते समय हर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ट्रंपकालीन दुनिया में संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं वैसे भी अपना असर छोड़ती नहीं दिख रही हैं। दरअसल, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता बनाए रखने की है। हालांकि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि युद्धों से त्रस्त दुनिया को इन संस्थाओं की जरूरत नहीं। लेकिन, जब ये संस्थाएं व्यवहार में वैश्विक राजनीति के प्रभाव से मुक्त नहीं दिख रही हों, तब यह उनकी नैतिक शक्ति और विश्वसनीयता को कमजोर ही करता है।



इसकी कल्पना सहज की जा सकती है। यह आशंका निराधार नहीं है कि जैसे-जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, कांग्रेस की गुटबाजी और जुताम-पैजार बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में टिकट के दावेदार बढेंगे, पदों की खींचतान तेज होगी और हर नेता अपने समर्थकों के साथ ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। अगर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी से अनुशासन को स्पष्ट लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, तो चुनावी तैयारी से ज्यादा ऊर्जा आपसी हिसाब चुकता करने में खर्च हो सकती है।

साथ ही इस पुरे विवाद को केवल अजय राय बनाम नए नेतृत्व की लड़ाई बताकर खत्म नहीं किया जा सकता। ममता चौधरी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अभद्रता हुई और उन्हें धमकाया गया। उन्होंने अजय राय पर दलित विरोधी व्यवहार का आरोप भी लगाया है। दूसरी ओर, अजय राय ने भी ममता चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई है। इसकी कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को दी गई है। समिति में अभिषेक दत्त,

महेन्द्र तिवारी

लोकतंत्र की जीवंतता केवल इस बात से तय नहीं होती कि संसद के भीतर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कितनी सार्थक बहस होती है, बल्कि इसकी असली कसौटी यह है कि संसद के बाहर सड़कों पर आम नागरिक की आवाज को कितनी गंभीरता और सहजता से सुना जाता है। देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल में स्थित जंतर मंतर पिछले 33 वर्षों से इसी लोकतांत्रिक चेतना, जन आक्रोश और नागरिक उम्मीदों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। किंतु अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जंतर मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया है। 28 अप्रैल 2022 के पुराने स्थायी आदेश में संशोधन करते हुए अब राजधानी में धरना और प्रदर्शन के लिए तीन नए स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मध्य दिल्ली का रामलीला मैदान, उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के कड़कड़झूमा स्थित व्यावसायिक केंद्र मैदान शामिल हैं। प्रशासन के इस एक निर्णय ने तीन दशकों से चली आ रही प्रतिरोध की एक पूरी परंपरा को विराम दे दिया है और साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों तथा प्रशासनिक व्यवस्था के बीच के द्वंद पर एक नई बहस छेड़ दी है।

जंतर मंतर का यह परिसर केवल 18वीं सदी के खगोलीय यंत्रों का स्मारक मात्र नहीं था, बल्कि यह आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका था। वर्ष 1993 से लेकर 2026 तक के अपने 33



वर्षों के सफर में इस छोटे से मार्ग ने अनगिनत ऐतिहासिक बदलावों की नींव रखी। चाहे वर्ष 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन हो, वर्ष 2012 में निर्भया कांड के बाद उमड़ा युवाओं का स्वतःस्फूर्त जनसैलाब हो, वर्ष 2015 में पूर्व सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन आंदोलन हो या फिर वर्ष 2023 में महिला पहलवानों का लंबा संघर्ष, जंतर मंतर ने हर वर्ग की पीड़ा को राष्ट्रीय पटल पर रखने का मंच प्रदान किया। देश के सुदूर कोनों से आने वाले किसानों, मजदूरों, छात्रों, शिक्षकों और वंचित वर्गों के लिए यह स्थान एक ऐसी अहसास पाते थे। संसद भवन से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहाँ उठने वाली हर आवाज की गूंज नीति निर्माताओं के कानों तक आसानी से पहुँच जाती थी।

इस ऐतिहासिक स्थल से प्रदर्शनों को हटाने के पीछे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अपने ठोस तर्क हैं। तात्कालिक कारणों पर नजर डालें तो वर्ष 2026 के जून और जुलाई माह में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुविता और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर लगभग 36 दिनों तक चला विशाल छात्र आंदोलन इस फैसले का मुख्य आधार बना। उस आंदोलन के दौरान जंतर मंतर की

अब्दुल हज़ान, रवि वर्मा और शमीना शफ़ीक भी शामिल हैं।

देखा जाये तो यहां कांग्रेस नेतृत्व के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ पार्टी को नेताओं के बीच अनुशासन कायम करना है, दूसरी तरफ महिला और दलित कार्यकर्ताओं की शिकायतों को निष्पक्षता से सुनना है। यदि किसी नेता के प्रभाव के कारण शिकायत दबती है, तो संगठन के भीतर बराबरी और सम्मान के दावों पर सवाल उठेंगे। और यदि जांच से पहले ही किसी को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो निष्पक्ष प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे। साथ ही अजय राय की नाराजगी का एक पहलू समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के रिश्तों से भी जुड़ा बताया जा रहा है। पार्टी के भीतर ऐसी चर्चा है कि अखिलेश यादव के साथ बेहतर तालमेल बैठाने की कवायद में प्रदेश नेतृत्व बदलने का फैसला लिया गया। अजय राय के समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते सहज नहीं रहे, जबकि प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा को गठबंधन के लिहाज से अपेक्षाकृत सुविधाजनक माना जाता है।

इसके अलावा, सोमवार को दिल्ली में राहुल गांधी के आह्वान पर निकले कांग्रेस के विरोध मार्च में अजय राय की गैरमौजूदगी ने भी अटकलों को हवा दी। जब प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव के बाद नाराजगी खुलकर सामने आ रही हो और पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम से दूर रहें, तो सवाल उठना लाजिमी है कि मामला सिर्फ पद का है या राजनीतिक भविष्य का भी। हालांकि अजय राय के सामने पिंडरा विधानसभा सीट का अपना सियासी हिसाब भी है। वह वहां से अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय रहना चाहते हैं। ऐसे में गुजरात की जिम्मेदारी स्वीकार

करना, यूपी में अपनी जमीन पर ध्यान देना या किसी दूसरे राजनीतिक विकल्प पर विचार करना, इन संभावनाओं के बीच उनकी अगली चाल पर सबकी नजर रहेगी। साथ ही यूपी कांग्रेस के सामने संकट केवल अजय राय की नाराजगी का नहीं है। संकट उस संगठनात्मक संस्कृति का है, जिसमें पद बदलते ही पुराने और नए नेतृत्व के बीच अविश्वास सिर उठाने लगता है। यदि हर बदलाव को प्रतिष्ठता की लड़ाई बना दिया जाएगा, तो संगठन का विस्तार कैसे होगा ? और यदि हर असहमति समर्थकों की भिड़ंत में बदल जाएगी, तो आम कार्यकर्ता अपनी जगह कहां तलाशेंगे ? उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी और बड़े नेताओं की तस्वीरों से नहीं चलती। बूथ पर कार्यकर्ता चाहिए, गांव में भरोसा चाहिए और टिकट न मिलने पर भी संगठन के साथ खड़े रहने की राजनीतिक संस्कृति चाहिए। पार्टी कार्यालय में जूते-चप्पल चलना इसी कसौटी पर कांग्रेस के सामने अपसहज सवाल खड़ा करता है। बहरहाल, अजय राय भाजपा में लौटेंगे या कांग्रेस उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देकर रोक लेगी, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के लिए इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या वह नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के बीच संगठन को बचा पाएगा ? क्योंकि यूपी की सियासत में चुनाव से पहले नाराजगी कोई नई बात नहीं। नई बात तब होगी, जब कोई पार्टी अपने नेताओं को यह समझा सके कि संगठन की कुर्सी निजी जागीर नहीं और पार्टी कार्यालय अखाड़ा नहीं होता। कांग्रेस ने अगर अनुशासन को कायम करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाये तो 2027 की चुनावी बिसात बिछने तक कांग्रेस में विरोधियों से मुकाबले की तैयारी कम और अपनों से हिसाब बराबर करने की कवायद ज्यादा दिखाई दे सकती है।

जंतर–मंतर से दूर होते प्रतिरोध के ठिकाने

सीमित क्षमता के विपरीत 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी जुट गए थे। जब इस भारी भीड़ ने संसद भवन की ओर कूच करने का प्रयास किया, तो सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई और पुलिस तथा छात्रों के बीच हुई झड़पों में 118 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों छात्र घायल हुए। इसके अतिरिक्त, हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और युवा संगठनों द्वारा फिर से जंतर मंतर पर बड़े धेराव की तैयारी की जा रही थी। नए संसद भवन और कर्तव्य पथ के आसपास अति विशिष्ट व्यक्तियों के निरंतर आवागमन और संवेदनशील मंत्रालयों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का मानना है कि इतनी कम दूरी पर अनियंत्रित भीड़ का जुटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम है। सुरक्षा के अलावा स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों की बड़बू कारण बनी हैं। जंतर मंतर राजधानी के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र कनाट प्लेस और जनपथ के ठीक बगल में स्थित है। जब भी यहाँ कोई बड़ा प्रदर्शन होता था, तो एहतियात के तौर पर आसपास की मुख्य सड़कों और रेल के भूमिगत स्टेशन बंद कर दिए जाते थे। इससे न केवल घंटों लंबा यातायात जाम लगता था, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों की गाड़ियां छूट जाती थीं। स्थानीय व्यापार मंडलों ने लंबे समय से यह शिकायत की थी कि लगातार होने वाले धरनों और नाकेबंदी के कारण कनाट प्लेस के व्यापार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूर्व में यह सुझाव दिया था कि प्रदर्शनों के लिए ऐसी खुली और बड़ी जगह तलाशी जानी चाहिए जहाँ आम जनजीवन प्रभावित

न हो तथा प्रदर्शनकारियों के लिए पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें।

किंतु इस प्रशासनिक सुविधा के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो नागरिक अधिकार संगठनों और संविधानविदों की चिंताएं अत्यंत गंभीर और विचारणीय हैं। राजधानी में सत्ता के केंद्र से जन आंदोलनों को दूर धकेलने की यह प्रवृत्ति नई नहीं है, बल्कि पिछले चार दशकों में विरोध का पता तीन बार बदला जा चुका है। वर्ष 1988 तक इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब देश के सबसे बड़े प्रदर्शनों का केंद्र हुआ करता था, जहाँ से संसद और राष्ट्रपति भवन सीधे दिखाई देते थे। अक्टूबर 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब 5 लाख किसानों ने एक सप्ताह तक बोट क्लब पर डेरा डाला, तो सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था का हवाला देकर वहां प्रदर्शनों पर स्थायी रोक लगा दी और वर्ष 1993 में जंतर मंतर को नया विकल्प बनाया गया। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का हवाला देकर जंतर मंतर पर भी आंशिक पाबंदियां लगाईं, और अब वर्ष 2026 में इसे पूरी तरह से सूची से हटा दिया गया है।

बोट क्लब से जंतर मंतर और अब जंतर मंतर से बुराड़ी तथा कड़कड़झूमा के मैदानों तक का यह सफर वास्तव में सत्ता के गलियारों से आम जनता की भींतिक और मनोवैज्ञानिक दूरी बढ़ने की कहानी है। लोकतंत्र में किसी भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का मूल उद्देश्य समाज का ध्यान आकर्षित करना और राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के जरिए अपनी बात देश के सामने रखना होता है।

रूस को रियायत, यूक्रेन पर दबाव ; ट्रंप की नीति पर सवाल

स्टीफन वॉल्फ

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस को लाखों टन डीजल बेचने की अनुमति देने के लिए जो समझौता किया है, वह अमेरिकी नीति से एक बड़ा विचलन तो है ही, यूक्रेन व यूरोप के हितों के विपरीत भी है। यह समझौता पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित उस कानून का भी सीधे तौर पर उल्लंघन करता है, जिसके तहत रूसी तेल व गैस का आयात करने वाले देशों पर नए अमेरिकी प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की अनुमति दी गई थी।

इस समझौते का समय भी दुर्भाग्यपूर्ण था। उस वक्त यूक्रेन और यूरोप का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मियामी में ट्रंप के दूतों स्टीव विट्कोफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत कर रहा था। चर्चा में कथित तौर पर अमेरिका के नए प्रस्ताव शामिल थे, जिनका मकसद साढ़े चार साल से जारी युद्ध में जल्द से जल्द तनाव कम करना था। खबरों के मुताबिक, बातचीत के दौरान अमेरिकी दूतों ने संकेत दिया कि रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। इस घोषणा ने यूक्रेन और यूरोप के अधिकारियों को हैरान कर दिया। नतीजतन, बातचीत उसी दिन बिना किसी समझौते के खत्म हो गई, जबकि इसे एक दिन और चलना था। अगर अमेरिका और रूस के बीच यह डीजल समझौता सिर्फ इंधन की आपूर्ति तक सीमित होता, तो इसे एक साधारण समझौता कहा जा सकता था। ट्रंप की घोषणा के मुताबिक, इसके तहत साठ लाख बैरल से कुछ कम डीजल की आपूर्ति होनी है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, यह मात्रा अमेरिका की करीब डेढ़ दिन की डीजल खपत के बराबर है।

इस समझौते से वैश्विक बाजार में डीजल की कीमतों पर शायद ही कोई खास असर पड़ेगा, भले ही रूस ट्रंप की घोषणा के मुताबिक इंधन की आपूर्ति कर सके। हालांकि, इस पर पहले से ही संदेह है, क्योंकि रूसी डीजल निर्यात में कमी मुख्य रूप से क्रैमलिन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध के कारण है। दरअसल, डीजल की कीमतों में



बढ़ोतरी मुख्य रूप से ईरान के खिलाफ ट्रंप की जंग का नतीजा है। ऐसे में, अगर इस समझौते का मकसद नवंबर की शुरुआत में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले डीजल की कीमतें घटाना है, तो इससे कोई बड़ा फायदा होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, यूक्रेन युद्ध पर इसके असर कहीं अधिक गंभीर और नुकसानदेह हो सकते हैं।

जनवरी 2025 में दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप का तरीका कीव पर धौंस जमाकर उससे रियायतें मनवाने का रहा है। हालांकि, ये कोशिशें काफी हद तक नाकाम रही हैं। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूस को कोई भी क्षेत्र सौंपने के प्रस्ताव को लगातार खारिज किया है। ट्रंप का डीजल समझौता भी यूक्रेन पर दबाव बनाने की एक और कोशिश ही है, ताकि वह अपने सबसे प्रभावी हथियारों में से एक का इस्तेमाल करना बंद करे। खबरों के मुताबिक, यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और मिसाइलों ने हाल के महीनों में रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। इससे रूस की तेल शोधन क्षमता में 60 फीसदी तक की गिरावट आई है।

हाल के हफ्तों में ट्रंप, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोकने का दबाव डाल रहे हैं। साथ ही, वह डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए ईरान युद्ध के बजाय यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि, इस मामले में कीव का रुख हमेशा एक जैसा ही रहा है। डीजल समझौते की घोषणा के बाद जेलेंस्की ने फिर कहा, ‘अगर रूस हमारे ऊर्जा ढांचे को नष्ट नहीं करता,

तो यूक्रेन भी रूसी तेल रिफाइनरियों में आग नहीं लगाएगा।’ यह वही प्रस्ताव था, जिसे जेलेंस्की ने 22 सितंबर को रखा था और जिसका ट्रंप ने भी समर्थन किया था। लेकिन, रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि केवल रिफाइनरियों पर हमले रोकने से कीमतें कम नहीं होंगी। इसके लिए रूसी ऊर्जा निर्यात पर लगे प्रतिबंध भी हटाने होंगे।

नौ अक्तूबर को ट्रंप द्वारा घोषित डीजल समझौते से रूस को प्रतिबंधों में ऐसी ही राहत मिलती है। इस तरह, पुतिन को ऊर्जा संकटों का वह आर्थिक लाभ मिल गया, जिसकी उन्हें जरूरत थी, जबकि उन्होंने इसके सैन्य पहलू पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। दरअसल, जब ट्रंप ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन, दोनों ‘ऊर्जा युद्धविराम’ पर सहमत हो गए हैं, पर दोनों देशों ने किसी भी समझौते से इन्कार किया, तो रूस ने ट्रंप की इस घोषणा का जवाब यूक्रेनी बिजली संयंत्र पर हमला करके दिया। डीजल समझौते की घोषणा के बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से और नजदीकी बढ़ते हुए यूक्रेन से कहा कि उसे ‘नया नेता चुनना चाहिए।’ वहीं, मियामी में सप्ताहांत पर हुई बातचीत से संकेत मिला कि अगर हमले जारी रहे, तो वाशिंगटन यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और उसे हथियार बेचने पर रोक लगा सकता है। हालांकि, अमेरिका ने इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

हाल ही में, यूक्रेन को अपने जवाबी अभियान ‘ऑपरेशन विवाल्डो’ में बड़ी सफलता मिली है। जानकारों का मानना है कि इससे पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से अहम डोनेट्स्क क्षेत्र पर कब्जा करने की रूस की कोशिशों को झटका लगा है। ऐसे में युद्ध का आर्थिक पहलू और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस घटनाक्रम ने पहले से कमजोर अमेरिका-यूरोप (ट्रांसअटलंटिक) संबंधों पर दबाव और बढ़ा दिया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कक्षस ने कहा कि ‘रूसी डीजल पर प्रतिबंध हटाने से मॉस्को को युद्ध जारी रखने के लिए और अधिक धन मिलेगा।’ लेकिन, यूरोप अब पहले के मुकाबले अमेरिकी डीजल पर ज्यादा निर्भर है।

लोकतंत्र का गला घोटने का शातिराना प्रयास

निर्मल रानी

चुनावी धांधली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से राजधानी दिल्ली लगातार प्रदर्शनों से जूझ रही है। 10 अक्टूबर को जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के समर्थन से जंतर मंतर सहित दिल्ली के कई प्रमुख स्थलों पर बड़े प्रदर्शन किये वहीं 12 अक्टूबर का दिन विपक्षी इण्डिया गठबंधन द्वारा बुलाये गए विशाल रैली व प्रदर्शन के नाम रहा। 12 अक्टूबर के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन को विपक्षी दलों की सबसे बड़ी रैली व प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस रैली व प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,राहुल गाँधी,प्रियंका गाँधी,विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव , एन सी पी नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना के संजय राउत, सी पी आई एम एल के दीपांकर भट्टाचार्य,आर जे डी के तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी आदि अनेक बड़े नेता शामिल हुये। इस प्रदर्शन के दौरान भी जब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर नेताओं को रोकने की कोशिश की, तो अखिलेश यादव, महूआ मोश्रा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में भी लिया। बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल इस मामले को लेकर याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

इस प्रदर्शन को रोकने या इसे विफल करने के लिये सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किये गए। बले प्रयोग से लेकर सड़कों पर नुकीली कोलें बिछाने, प्रदर्शनकारियों से लेकर अनेक आम राहगीरों तक को गिरफ्तार करने की अनेक घटनाएं देखने को मिलीं। कनाट प्लेस से लेकर संसद भवन तक का इलाक़ा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। देश के इतिहास का यह पहला प्रदर्शन था जिस

कवर करने से रोकने की गरूज से अनेक प्रमुख मीडिया घरानों के पत्रकारों से लेकर कई स्वतंत्र व सोशल मीडिया जर्नलिस्ट्स व यू ट्यूबर्स को भी हिरासत में लिया गया। कई के साथ मारपीट भी की गयी। बी बी सी सहित अनेक पत्रकारों के साथ पुलिस बदसलूकी से पेशा आती दिखाई दी। जिन मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को दिल्ली में प्रदर्शन कवर करने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था उममें बिजनेस स्टैंडर्ड,नवभारत टाइम्स,रायटर्स के अलावा स्कॉल, न्यूज़ लॉन्ड्री,बूम,एमओ,मॉलिटिव्स इंडिया,उत्प चश्मा आदि कई पत्रकार शामिल हैं। जाने माने पत्रकार परंजाय गुहा ठाकुरता को भी दिल्ली में जबरन हिरासत में लिया गया जबकि ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार को अहमदाबाद में व स्कॉल के एक अन्य पत्रकार को पुणे में हिरासत में लिया गया। नवरात्रि के पहले ही दिन हो रहे थे? भारत का संविधान पत्रकारों को पीटा,घसीटा गया और हिरासत में लिया गया। यहाँ तक कि कई महिला पत्रकारों ने तो पुलिस पर यौन हमले का भी आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या जनहित के कार्यक्रमों को कवर करना कोई अपराध है जिसकी वजह से पुलिस को यह सब करना पड़ा ? जबकि इस प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए पत्रकार पेशेवर तरीक़े से अपना काम अंजाम दे रहे थे? भारत का संविधान पत्रकारों के रिपोर्टिंग करने, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने और जनहित के मुद्दों को नागरिकों के सामने लाने के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19(1)(ए) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।और प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी अनुच्छेद का हिस्सा माना गया है। ऐसे में कानून व्यवस्था के नाम पर इस तरह का तानाशाही रवैया ग़ैर संवैधानिक नहीं तो और क्या है ? क्या इसी भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल मंदर ऑफ़ डेमोक्रेसी, बताया था बल्कि अपनी बातों के समर्थन में मीडिया से जुड़े कुछ आंकड़े भी बताए थे ?



पेंच पार्क में दिखते हैं कुदरत के अनोखे रंग



दूसरे से सटे नहीं हैं और न ही आमने-सामने हैं। यह एक छोटी बस्ती की तरह चारों तरफ दोमंजिला शक्ल में फैले हुए हैं।

नागपुर और सिवनी के बीच खवासा गांव उतर कर मात्र 10 किलोमीटर अंदर जाकर जब पेंच का जीवन तबियत से जीने की इच्छा हो तो जरूरी है कि आप चश्मा ले जाएं, दूरबीन भी और कैमरा भी। जीप से घूमते समय पानी की बोतल साथ रखें। खाने-पीने के लिए गेट पर काफी रेस्तरां हैं साथ ही वन विभाग की कैंटीन और रेस्ट हाउस भी यहां उपलब्ध हैं।

मौसम कोई भी हो, पेंच में सुबह-सुबह सर्दी का एहसास जरूर होता है। सर्दियों में शाम भले ही किपलिंग कोर्ट के अंदर कमरे में कुछ सोचते, गुनगुनाते, थिरकते या नीचे मैदान में बैठ साथी पर्यटकों से बातचीत करते गुजारी जाए लेकिन गर्मियों की शाम में अगर बगैर दीवारों वाले तितली रेस्तरां में कुछ ठंडा-गरम पिया जाए तो पेंच आने की कीमत वसूल हो जाती है।

महाराष्ट्र के नागपुर और मध्य प्रदेश के सिवनी के बीच ‘पेंच नेशनल पार्क’ ऐसी जगह है जहां रखे व्यवहार वाला आदमी भी कुछ दिन रुक जाए तो वह भी काव्यात्मक लहजे में बातें करने लगेगा। पेंच की खूबसूरती को समझने के लिए 292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस घने जंगल में आपको घूमना पड़ेगा।

जिन जगहों पर कुदरत दिल से मेहरबान रही है

उनमें से पेंच भी एक है। पेंच आने वाले पर्यटकों का पहला सामना अपनी उछलकूद में मग्न बंदरों से होता है। कच्ची मगर सलीकेंदार सड़क के चारों ओर घने झुरमुटों में से स्वच्छंद विचरते हिरण, सांभर और चीतल जरूर टुमक कर पर्यटकों का स्वागत करते हैं मगर अपनी उत्सुक निगाहों को आप से हटा कर कुलाचें भरने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। हर दूसरे मोड़ पर ये दोबारा

आपके सामने नजर आ जाते हैं।

पेंच में शेर का दिखना मौके की बात है। यहां विचरते समय बीच-बीच में आपको नीलगाय, जंगली भैंसा, जंगली सूअर और जंगली कुत्ता आदि के साथ ही अन्य जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे।

पेंच में कुछ घंटे गुजरने के साथ ही आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि स्वच्छ हवा या आक्सीजन

कोडैकनाल भारत का एक आकर्षक पहाड़ी पर्यटन स्थल है जो तमिलनाडु राज्य में बसा डिंडागुल जिले का एक शहर है। यह समुद्र तल से 2133 मीटर की ऊंचाई पर एक पठार के ऊपर है। तमिल में कोडैकनाल का अर्थ वन का उपहार है। कोडै शब्द के चार अलग-अलग अर्थ होते हैं- पहला ‘जंगल का अंतिम छोर’, दूसरा ‘लताओं का जंगल’, तीसरा ‘गर्मियों का जंगल’ और चौथा ‘जंगल का उपहार’। यहां की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे ‘हिल स्टेशनों की राजकुमारी’ भी कहते हैं

कोडैकनाल हिल रिजॉर्ट अपनी सुंदरता और शांत वातावरण से सबको सम्मोहित कर लेता है। यहां घूमने का मजा कुरिंजी नामक फूल के खिलने के समय दुगुना हो जाता है। हालांकि यह फूल बारह साल में एक बार खिलता है। यहां के लोग कुरिंजी के फूल को देखना अपनी शान समझते हैं। जब यह खिलता है तो पहाड़ियों की सुंदरता देखते बनती है। इसकी खुशबू मदहोश कर देने वाली होती है। विशाल चट्टान, शांत झील, फलों के बागीचे और पाइन के जंगलों से आती शुद्ध हवा यहां के वातावरण को सुगंधित और गुलजार बना देती है। कोडैकनाल का उल्लेख ईसा पूर्व के संगम साहित्य में मिलता है। पलानी हिल्स के आसपास के क्षेत्र में उस समय पेलियंस और पुलयंस नामक आदिम जनजाति निवास करती थी। 1845 में अंग्रेजों ने यहां हिल स्टेशन स्थापित किया था। ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों का यह पसंदीदा हिल स्टेशन था। कोडैकनाल की स्थापना 1863 में हुई थी। इस खूबसूरत शहर के दर्शनीय स्थल-

कोडैकनाल झील

इस खूबसूरत सितारानुमा झील का निर्माण एक अंग्रेज ने किया था। जो 60 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसके चारों ओर की हरियाली पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस झील का बोट क्लब रोमांचक रेसिंग ट्रिप की सुविधा उपलब्ध कराता है।

कोर्कर्स वाक

लेफ्टिनेंट कोकर के नाम से इस स्थान का नाम कोर्कर्स वाक पड़ा। कोकर ने कोडैकनाल का मानचित्र तैयार किया था। यह शहर से एक किलोमीटर दूर मनमोहक पर्यटन स्थल है। यहां से आसपास की पहाड़ियों तथा मट्टुरै शहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैदानों से खूबसूरत दिलकश नजारों का लुत्फ लिया जा सकता है। यहां की प्रसिद्ध पिलर रॉक्स चट्टानें



वनों का सुंदर उपहार कोडैकनाल

कोडैकनाल से 7.4 किलोमीटर दूर हैं। ये 122 मीटर ऊंची है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। यह स्थान पिकनिक के लिए भी उपयुक्त है।

ब्रायंट पार्क

बेरियम झील के पूर्व दिशा में फैला ब्रायंट पार्क स्थित है। यह पार्क फूलों तथा संकर प्रजाति के विभिन्न पेड़-पौधों के लिए जाना जाता है। यहां एक ग्लास हाउस में विभिन्न किस्म के फूल खिले रहते हैं। मई महीने में यहां उद्यान मेला लगता है।

बेरियम झील

यह खूबसूरत झील पिकनिक के लिए लोकप्रिय स्थल है। प्राकृतिक सुंदरता से भरी यह झील कोडै कनाल बस स्टेशन से 21 किलोमीटर दूर है। इस झील से पेरियाकुलम नगर को पानी की सप्लाई होती है। झील की खोज और सुधार कार्य ब्रिटिश आर्मी कर्नल हेमिल्टन द्वारा 1864 में किया गया था।

शेनबागानूर संग्रहालय

झील से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह संग्रहालय स्थित है। इसकी देखरेख सेक्रेड हार्ट कॉलेज द्वारा की जाती है। यहां का आर्किडोरियम भारत के सबसे बेहतर आर्किडोरियम में से एक माना जाता है।

कुरिंजी अंदावर मंदिर

यह मंदिर कोडैकनाल से 3.2 किलोमीटर दूर है। यहां पर ‘लार्ड मुरुगन’ की एक आकर्षक प्रतिमा रखी हुई है। यहां से पलानी पहाड़ियों तथा वैगाई डैम का खूबसूरत दृश्य मन को मोह लेता है।

बीयरशोला फाल

यह खूबसूरत पिकनिक स्थल कोडैकनाल से 16 किलोमीटर दूर है। यहां अक्सर भालुओं को पानी पीते देख जा सकता है। भालुओं की उपस्थिति के कारण इस झरने का नाम बीयरशोला पड़ा।

सिल्वर कासकेड प्रपात

यह आकर्षक जलप्रपात कोडैकनाल झील से 8 किलोमीटर दूर है। झील का अतिरिक्त जल 180 फीट की ऊंचाई से झरने के रूप में गिरता है। यहां के शांत और सौम्य वातावरण का पर्यटक भरपूर आनंद लेते हैं।

बोट क्लब

यह बोट क्लब 1910 में स्थापित किया गया था। 1932 से पहले यह आम लोगों और पर्यटकों के लिए नहीं था। मात्र कुछ चुनिंदा सदस्य ही बोटिंग का आनंद ले सकते थे। बाद में पर्यटकों और आम लोगों को भी सुविधा दे दी गई।

वेधशाला

कोडैकनाल से 3.2 किलोमीटर दूर स्थित इस वेधशाला का निर्माण 1899 में किया गया था। 2347 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह वेधशाला कोडैकनाल की सबसे ऊंची जगह है। यहां से प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखता है।

टेलीस्कोप हाउस



घाटी और उसके आसपास की सुंदरता को देखने के लिए दो टे लीस्कोप हाउस स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा सौर भौतिक वेधशाला, ग्रीन वैली व्यू, गुना गुफाएं, डॉल्फिन नोज, थालाइयर झरना आदि जगहों की सैर कर सकते हैं। फलों में नाशपाती के लिए यह जगह प्रसिद्ध है। चॉकलेट प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग माना जाता है। साहसिक गतिविधियों में ट्रेकिंग, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग का आनंद लिया जा सकता है।

कब और कैसे जाएं

सालभर मौसम अच्छा रहता है। वैसे, अच्छा समय अप्रैल से अगस्त उत्तम है। सर्दियों के दौरान इस जगह की यात्रा अच्छी रहती है। निकटतम हवाई अड्डा मट्टुरै है, जो यहां से 120 किलोमीटर दूर है। यहां से बस या टैक्सी द्वारा कोडैकनाल पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कोडै रोड है, जो कोडैकनाल से 80 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग के लिए दक्षिण भारत के कई मुख्य शहरों से सीधी बस सेवा द्वारा जुड़ा है।

अरब सागर की गोद में बैठे छोटे ये द्वीप अपनी सुंदरता में अद्वितीय और आकर्षक हैं। ये भारत के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। मुख्य भूमि से दूर इनका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रदूषणमुक्त वातावरण, चारों ओर समुद्र और इसका पारदर्शी तल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।

समुद्री जल में तैरती असंख्य प्रजातियों की रंगबिरंगी मछलियाँ इन द्वीपों की सुंदरता को चार चाँद लगा देती हैं। हर द्वीप पर नारियल व पाम के झूमते हरे-भरे वृक्ष हैं। और साथ है कोरा-कुँवारा समुद्र जिसका नीला पानी आपको अनोखी पवित्रता का अहसास कराता है।

लक्षद्वीप भारत के एकमात्र मूँगा द्वीप हैं। इन द्वीपों की श्रृंखला मूँगा एटोल हैं। एटोल मूँगे के द्वारा बनाया गई ऐसी रचना है जो समुद्र की सतह पर पानी और हवा मिलने पर बनती है। सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों में मूँगा जीवित रह सकता है। यहाँ के निवासी केरल के निवासियों से बहुत मिलते-जुलते हैं। यह द्वीप पर्यटकों का स्वर्ग है। यहाँ का नैसर्गिक वातावरण देश-विदेश के सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। अब केंद्र सरकार इन द्वीपों का पर्यटन की दृष्टि से तेजी से विकास कर रही है।

समुद्र जल में जो जीव सृष्टि है, वह धरातल के ऊपर के प्राणियों से कम सुंदर और आकर्षक नहीं है। ये द्वीप प्रकृति की एक अद्भुत देन हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ की धरती का निर्माण मूँगों द्वारा किया गया। उन्होंने ही मानव के रहन-सहन के उपयुक्त बनाया। यह द्वीप पर्यटकों का स्वर्ग है। यहाँ का नैसर्गिक वातावरण देश-विदेश के सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है।

द्वीप

अगत्ती लक्षद्वीप का बेहद खूबसूरत लैंगून में से



है। यहाँ एयरपोर्ट भी है। लक्षद्वीप में यहीं से प्रवेश किया जाता है। यहीं पर 20 बिस्तरों वाला एक पर्यटक काम्पलैक्स भी है।

बंगारम

औसू के आकार के इस द्वीप में चारों ओर क्रीमी रंग की रेत बिखरी हुई है। लक्षद्वीप के हर द्वीप की तरह यहाँ भी नारियल के वृक्ष सघन मात्रा में हैं जो दिन की तीखी गर्मी में भी ठंडक देते हैं।

कवरत्ती

कवरत्ती यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। यह सबसे अधिक विकसित भी है साथ ही यहाँ द्वीपवासियों के अलावा अन्य लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। पूरे द्वीप में 52 मस्जिद हैं, सबसे खूबसूरत मस्जिद है उज़्र मस्जिद। कहा जाता है कि यहाँ के पानी में चमत्कारी शक्ति है।

इस द्वीप में एक्वेरियम भी है जिसमें सुंदर मछलियों की प्रजातियाँ हैं। यहाँ कॉच की तली वाली नौका में बैठकर आप समुद्री दुनिया का नजारा

सागर किनारे लक्षद्वीप

ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वाटर स्पोर्ट्स जैसे केयाकिंग, कनोइंग और स्नोरकेलिंग का मजा भी ले सकते हैं।

कालपेनी

यहाँ तीन द्वीप हैं जिनमें आबादी नहीं है। इनके चारों ओर लैंगून की सुंदरता देखने लायक है। कुमेल एक खाड़ी है जहाँ पर्यटन की पूरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ से पिती और थिलक्कम नाम के दो द्वीपों को देखा जा सकता है। यहाँ आप तैर सकते हैं, रीफ पर चल सकते हैं, नौका में बैठकर घूम सकते हैं और कई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं।

कदमठ

एक जैसी गहराई और दूर अनंत तक जाते किनारे कदमठ को स्वर्ग बनाते हैं। यही एकमात्र द्वीप है जिसके पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर लैंगून हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की बेहतरीन सुविधाएँ हैं।

मिनिर्काँय

यह कवरत्ती से 200 किमी दूर दक्षिण में है। मालदीव के करीब होने के कारण यहाँ भिन्न संस्कृति के दर्शन होते हैं। मिनिर्काँय नृत्य परंपरा के मामले में बेहद समृद्ध है। विशेष

अवसर पर यहाँ लावा नृत्य किया जाता है। यहाँ खासकर तूना मछली का शिकार और नौका की सैर आनंददायी है। अँग्रेजों के द्वारा 1885 में बनवाया गया प्रकाश स्तंभ देखने लायक है, पर्यटक यहाँ ऊपर तक जा सकते हैं।

कैसे जाएं

हवाई मार्ग से कोचीन से अगत्ती द्वीप तक सीधी हवाई सेवा है। अगत्ती से हेलिकॉप्टर या बोट के माध्यम से आगे जाया जा सकता है। दूसरे द्वीपों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। पानी के जहाज से केरल के कोचीन से जहाज की सेवा भी उपलब्ध है।

कब जाएं

अक्टूबर-नवंबर में यहाँ बारिश होती है और पानी के जहाज चलना बंद हो जाते हैं। फिर भी हेलिकॉप्टर के माध्यम से आप यहाँ जा सकते हैं। इन दिनों मौसम कुछ ठंडा हो जाता है लेकिन अन्य दिनों में गर्मी रहती है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलीं भाजपा सांसद

नई दिल्ली। 15 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रभारी डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी के साथ-साथ सांसद बांसुरी स्वराज और रूप कुमारी चौधरी शामिल थीं। उन्होंने एक पत्र सौंपा, जिसमें इन आरोपों की गंभीरता, विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच और अकोइजम के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का जिक्र किया गया था। पत्र में कांग्रेस नेतृत्व की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि यह मामला महिलाओं के सम्मान, छात्राओं की सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में नैतिक जवाबदेही और राजनीतिक दलों के आचरण से जुड़ा है।

पाकिस्तान की आतंकी हरकत पर भारत करेगा और बड़ा हमला

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर को कहा कि शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति बनाए रखने के लिए ताकत और क्षमता का होना जरूरी है। नई दिल्ली में टाइम्स नेटवर्क नेशनल डिफेंस कॉन्क्लेव 2026 में बोलते हुए, सिंह ने कहा कि शांति की कामना करना हमारी सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। हमारी संस्कृति हमें बातचीत, सह-अस्तित्व और शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता दिखाती है। लेकिन शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। शांति बनाए रखने के लिए ताकत और क्षमता का होना भी जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आगे कोई और आतंकी गतिविधि होती है, तो भारत पहले के ऑपरेशनों से भी बड़ा हमला करेगा। सिंह ने आतंकी हमलों के खिलाफ भारत की निर्णायक जवाबी कार्रवाइयों को याद किया।

बांग्लादेश मॉडल से अराजकता फैलाने की कोशिश : भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) की अध्यक्ष नेहा बोरा का समर्थन करके लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से राजनीतिक प्रतिरोध की बात करने के पीछे असल मकसद सत्ता परिवर्तन करना है। गुरवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, भंडारी ने बांग्लादेश में हुए विरोध-प्रदर्शनों पर नेहा बोरा की टिप्पणियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान से जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों की विचारधारा एक ही है, जिसका मकसद भारत में अराजकता फैलाना है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर यह आरोप भी लगाया कि चुनावी रास्ते से सत्ता हासिल करने में नाकाम रहने के बाद, वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

आप ने दिया सीजेपी के तिरंगा लहराओ कार्यक्रम को समर्थन

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कर्नाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तिरंगा लहराओ कार्यक्रम को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। पहले यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर को होना था, लेकिन सीजेपी कार्यकर्ताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी, और कार्यकर्ता अभिजीत दिपके को मिली धमकियों के बाद इसे टाल दिया गया था। उम्मीद है कि आप, सीजेपी के इस आह्वान के समर्थन में बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को जुटाएगी। साथ ही, अन्य संगठनों के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। अभिजीत दिपके ने रांका और दास की गिरफ्तारी के तीसरे दिन, उन्हें हिरासत में रखे जाने पर स्वाल उठाया। उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और बदलाव के लिए लड़ने के कारण जेल में डालने के लिए अधिकारियों की आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में, दिपके ने लिखा कि आशु और सौरव की अवैध गिरफ्तारी का आज तीसरा दिन है।

सीईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पहली बार शामिल हुई टीवीके

चेन्नई। देशभर में पिछले कुछ दिनों से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब इस आंदोलन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाले तमिलगमा वेट्टी कजगम (टीवीके) भी शामिल हो गई है। गुरवार को पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के साथ चेन्नई में मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर और तमिलनाडु कांग्रेस कमेट्री (टीएनसीसी) ने किया, जिसमें सभी सात घटक दलों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। तीन अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के बाद टीवीके पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाले अभियान में शामिल हुई।

लद्दाख को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तोहफा

3,350 करोड़ रुपये की लागत वाली 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचा, सामरिक सड़क संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, विरासत संरक्षण और जल सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मोदी इन परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नये यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके अनुसार 23,800 वर्ग मीटर में फैले इस आधुनिक टर्मिनल को प्रति वर्ष 35 लाख यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है।

बयान के अनुसार मोदी सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की निर्मित 298 किलोमीटर लंबी निम्न-पडुम-दारचा सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया। बयान में कहा गया है कि लेह के निम्न को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग प्रदान करने को तैयार है और श्रीनगर-लेह तथा मनाली-लेह राजमार्गों का पूरक है।

इसके अनुसार शिनकुन ला दर्रे समेत चुनौतीपूर्ण हिमालयी भूभाग से गुजरने वाली यह सड़क एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका रणनीतिक महत्व संश्लेष बलों के लिए परिचालन गतिशीलता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स सहायता को मजबूत करने में निहित है। इससे जांस्कर के निवासियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बाजार और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में भी



लाभ होगा। बयान के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और लद्दाख की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के प्रयासों के तहत, प्रधानमंत्री 9 मेगावाट की हनु लघु जलविद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल-सर्किट दाह-हनु-खालत्सी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बिजली आपूर्ति अवसंरचना को मजबूत करेंगी और लद्दाख के विद्युत नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार करेंगी।

ये परियोजनाएं क्षेत्र के जलविद्युत संसाधनों का दोहन करने और ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी मिशन अमृत सरोवर के उद्देश्यों के अनुरूप, जल संरक्षण के माध्यम से लद्दाख की अनूठी भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन किया।

पिएम मोदी ने लद्दाख के युवाओं को दी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की खेल क्षमताओं पर जोर दिया और आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स तथा पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए वहां

के युवाओं की सराहना की। लगभग 3,350 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण के लिए आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे, रणनीतिक सड़क संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए सुधारों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि लद्दाख में खेलों के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे खेलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्थानीय खिलाड़ियों को समर्थन देने की पहल के बारे में बताते हुए मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई खेल नीति के जरिए खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलें, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल कर सकें।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारा विशेष ध्यान लद्दाख की युवा पीढ़ी पर है। हम चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई तकनीकें सीखने के अवसर मिलें और उन्हें अन्य शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। इसीलिए लेह में एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सेंटेलाइट कैम्पस के प्रस्तावों का भी जिक्र किया और कहा कि इन पहलों से लद्दाख के युवाओं को उनके अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा, शोध और नए कौशल सीखने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

सेंसेक्स 1533 अंक उछला निफ्टी 22997 पर बंद

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बुल का दबदबा दिखा। बेंचमार्क इंडेक्स 2-2 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1533 अंक ऊपर 74315 पर बंद हुआ, जो सेशन के दौरान 74330 तक उछला। निफ्टी भी कारोबारी सेशन में 23000 का अहम स्तर पार किया। अंत में इंडेक्स 374 अंकों की उछाल के साथ 22997 पर बंद हुआ। निफ्टी में 41 शेयर चढ़कर और 8 शेयर गिरकर बंद हुए। निफ्टी में टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3.4 फीसदी से 4.7 फीसदी तक की तेजी रही, जो टॉप गेनर रहे। वहीं, नेस्ले इंडिया का शेयर 7.7 फीसदी गिरकर बंद हुआ, जो इंडेक्स का टॉप लुजर रहा। गुप्तावर का भारतीय शेयरों में तेज वृद्धि ऑटो और आईटी शेयरों के नेतृत्व में हुई। निजी बैंकों और वित्तीय सेवाओं के शेयरों ने भी बाजार को समर्थन दिया।

नेस्ले इंडिया का मुनाफा दूसरी तिमाही में 36 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। नेस्ले इंडिया ने सितंबर तिमाही (FY27) के नतीजे गुरुवार को जारी कर दिए। कंपनी की आय और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, नतीजे आने के बाद भारी बिकवाली के चलते कंपनी के शेयर 7% तक टूट गए हैं। सितंबर तिमाही में नेस्ले इंडिया की आय 20 फीसदी से अधिक और मुनाफा 36 फीसदी से अधिक बढ़ा है। नेस्ले इंडिया को जारी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 68,086 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। यह पिछले साल समान तिमाही में कंपनी की 56,491 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले 20.50 फीसदी अधिक है। वहीं, कंपनी का टैक्स पश्चात मुनाफा 36% से अधिक बढ़कर 10,267 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछली सितंबर तिमाही में कंपनी को 7,532 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मजबूत नतीजों के बावजूद कंपनी के शेयरों में बिकवाली नजर आ रही है।

देश के आयात और निर्यात के आंकड़ों में इजाफा

नई दिल्ली। भारत का निर्यात सितंबर में 23.04 प्रतिशत बढ़कर 44.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्यात बढ़ने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही सितंबर में आयात का आंकड़ा भी बढ़ गया है। देश का आयात 8 प्रतिशत बढ़कर 74.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत के निर्यात में सितंबर माह में 23 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह बढ़कर 44.4 अरब डॉलर हो गया है। इसी अवधि में देश का व्यापार घाटा भी घटकर 30.21 अरब डॉलर पर आ गया है। यह जानकारी बृहस्पतिवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों में शामिल आई है। सितंबर में देश का आयात भी 8 फीसदी बढ़कर 74.61 अरब डॉलर हो गया। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से सितंबर अवधि के दौरान निर्यात में 18.51 फीसदी की उछाल देखी गई।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री सितंबर में 21.8 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। देश में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर 21.8 प्रतिशत बढ़कर 4,54,574 इकाई हो गई। उद्योग संगठन सियाम ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सितंबर 2025 में थोक बिक्री 3,73,347 इकाई रही थी। सियाम के अनुसार, दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री पिछले महीने 13.5 प्रतिशत बढ़कर 24.63 लाख इकाई हो गई, जबकि सितंबर 2025 में यह 21.70 लाख इकाई थी। वहीं सितंबर में तिपहिया वाहनों की थोक बिक्री 16 प्रतिशत बढ़कर 98,162 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 84,635 इकाई थी।

स्टेल प्रमुख समाचार

वेस्टइंडीज से हार, अख्यर ने गेंदबाजी को माना का जिम्मेदार

हैदराबाद। चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हार के बाद, भारतीय कप्तान श्रेयस अख्यर ने कहा कि उनकी टीम सही लाइन और लेन में गेंदबाजी नहीं कर पाई। वहीं, वेस्टइंडीज ने बीच के ओवरों में पिच से मिल रही मदद का फायदा उठाया, जब पिच थोड़ी धीमी हो गई थी। इस दौर पर शाई होप के चौथे शतक और कीमो पॉल के पांच विकेटों की बदौलत, वेस्टइंडीज ने 248 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए भारत को 23 रनों से हरा दिया। अब सीरीज 2-2 की बराबरी पर है, जिससे 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली आखिरी मैच काफी रोमांचक हो गया है।

भारत की शुरुआत संजू सैमसन के आक्रमक अर्धशतक के साथ हुई, लेकिन उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा को शुरुआती कुछ ओवरों में स्ट्राइक ही नहीं मिल पाई। संजू के आउट होने के बाद भारत के पतन की शुरुआत हुई, क्योंकि बाकी बल्लेबाज इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरी लय को बनाए नहीं रख सके। मैच के बाद हुई बातचीत में हार के बारे में बात करते हुए, अख्यर ने कहा कि इसकी शुरुआत गेंदबाजी से हुई।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम अपनी लाइन और लेंथ को सही से लागू नहीं कर पाए। 250 रनों का पीछा करते समय, आपको एक तय तरीके से आगे बढ़ना होता है। इसलिए, पीछा करते समय हमारा जो अप्रोच था, वह मुझे अच्छा लगा। लेकिन बदकिस्मती से, हम गेंदबाजी में अपनी योजनाओं को सही से लागू नहीं कर पाए, और यहीं पर हम थोड़े पीछे रह गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या अभिषेक के स्ट्राइक न ले पाने की वजह से भारत को हार मिली, तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, उस समय भी हमारा रन रेट 12 प्रति ओवर चल रहा था। बात बस इतनी है कि उन्होंने (वेस्टइंडीज ने) अपनी योजना को अच्छे से लागू किया।

महेन्द्र तिवारी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत उसाहवर्धक और सकारात्मक संकेत है। वैश्विक पटल पर जब कई बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी, महंगाई और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हैं, तब भारत की विकास दर में इस तरह का सकारात्मक संशोधन देश की आर्थिक नीतियों और मजबूत आधारभूत संरचना की सफलता को प्रमाणित करता है। यह केवल एक संख्यात्मक वृद्धि नहीं है, बल्कि यह विश्व समुदाय के उस अटूट भरोसे का प्रतीक है जो उसने भारत की आर्थिक संभावनाओं पर जताया है। सात प्रतिशत की यह जादुई विकास दर भारत को दुनिया की सबसे तेजी

से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे ऊपर रखती है और यह स्पष्ट करती है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का आर्थिक पहिया तेज गति से घूम रहा है। इस शानदार आर्थिक वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण देश की अपनी मजबूत घरेलू मांग है। पश्चिमी देशों की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से केवल निर्यात निर्भर नहीं है, बल्कि यहां का विशाल मध्यमवर्ग और उत्तक्री उपभोग क्षमता अर्थव्यवस्था को एक मजबूत ढाल प्रदान करती है। जब वैश्विक बाजारों में मांग कम होती है, तब देश के भीतर की खपत उत्पादन को गिरने नहीं देती। पिछले कुछ वर्षों में लोगों की क्रय शक्ति में जो सुधार आया है, उसने बाजार में उत्पादों और सेवाओं की मांग को निरंतर बनाए रखा है। यह घरेलू मांग ही है जिसके कारण छोटे से लेकर बड़े उद्योगों तक का चक्र सुचारु रूप से चल रहा है।



ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत बढ़ने से विनिर्माण और खुदरा व्यापार को भारी लाभ मिल रहा है, जो अंततः सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। घरेलू मांग के साथ ही सेवा क्षेत्र इस विकास यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। भारत का सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा, न केवल देश के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धाक जमा रहा है। तकनीक के निरंतर विस्तार और नवाचार ने भारतीय उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाया है। वित्तीय

सेवाओं के आधुनिकीकरण और लेनदेन की नई तकनीकी प्रणालियों ने भी व्यापार को आसान और पारदर्शी बनाया है। सेवा क्षेत्र का लगातार विस्तार न केवल विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा रहा है, बल्कि यह लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती पैठ उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है।

सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर किया जा रहा भारी पूंजीगत व्यय भी इस सात प्रतिशत की वृद्धि का एक प्रमुख वाहक है। नई सड़कों, राजमार्गों, रेलवे मार्गों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण से न केवल देश के विभिन्न हिस्से आपस में बेहतर तरीके से जुड़ रहे हैं, बल्कि इससे माल ढुलाई और व्यापार की लागत में भी भारी कमी आ रही है। बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया धन अर्थव्यवस्था में कई गुना अधिक प्रभाव

डालता है। इससे निर्माण सामग्री उद्योगों को सीधा लाभ मिलता है और दिहाड़ी मजदूरों से लेकर तकनीकी विशेषज्ञों तक हर स्तर पर रोजगार का सृजन होता है। सरकार को यह दूरदर्शी सोच अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान कर रही है, जिससे भविष्य में विकास की रफ्तार को और भी तेज किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र में जान फूंकने के लिए लागू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन जैसी योजनाओं का भी सकारात्मक असर दिखने लगा है। देश को वैश्विक विकास का केंद्र बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अब संचार उपकरणों से लेकर रक्षा सामग्री और बिजली से चलने वाले उपकरणों तक का निर्माण बड़े पैमाने पर देश के भीतर ही हो रहा है। इससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है और व्यापार घाटा भी सुधर रहा है।

